साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र

जयपुर से प्रकाशित

उम्मीद की एक नई रोशनी

आवाज़ ए तसनीम

tasneemtv.official@gmail.com

آوازِ تسنیم

PRGI No. RJBIL/25/A1815

www.tasneemtv.com | वर्षः 02 / अंकः 18 | जयपुर, सोमवार, 23 नवंबर , 2026 | पृष्ठः 8 | मूल्यः 2 रूपए | प्रातः कालीन

जयपुर में पंचायत चुनाव में वोटों की चौंकाने वाली गणित

तीसरे नंबर की पार्टी ने बनाया बोर्ड; 43% वोट लाकर कांग्रेस ने जीती 56% सीटें

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। जयपुर में पंचायत चुनाव के रिजल्ट के आंकड़े कुछ चौंकाने वाले हैं। वोट प्रतिशत सबसे कम रहने के बावजूद तीसरी पार्टी ने पंचायत समिति में खुद का बोर्ड बना दिया। वहीं जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, वह दूसरे-तीसरे नंबर पर रही। जयपुर में 22 पंचायत समितियों में मिले वोटों की गणित देखें तो कांग्रेस ने करीब 43 फीसदी वोट लेकर 56 फीसदी सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा 35 फीसदी वोट लेकर भी महज 23 फीसदी सीटों पर सिमट गई।

सबसे बड़ा उलटफेर सांगानेर पंचायत समिति में हुआ। जहां वोट पाने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) तीसरे नंबर पर रही, जबकि सीटें सबसे ज्यादा जीतकर पहले नंबर पर रही। सांगानेर में RLP को कुल 18320 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 18872 और बीजेपी को 20941 वोट। यहां 15 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 और आरएलपी को 8 सीटें मिली, जबकि एक अन्य के खाते में गई।



आंधी पंचायत समितिः 52% वोट से कांग्रेस ने जीती 90 फीसदी सीटें

आंधी पंचायत समिति में कांग्रेस ने 52.12 प्रतिशत (33243) वोट हासिल किए। यहां कांग्रेस को 19 में से 17 सीटें मिली। यानी करीब आधे वोटों ने कांग्रेस को लगभग 90 प्रतिशत सीटें दिला दीं।

इसी तरह जमवारामगढ़ में कांग्रेस को 49.19 प्रतिशत वोट मिले और उसने 23 में से 18 सीटें जीत लीं। बस्सी में कांग्रेस ने 46.46 प्रतिशत वोट लेकर 25 में से 18 सीटें हासिल कीं। इन क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त केवल वोटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीटों में भी निर्णायक साबित हुई।

RLP ने पांच पंचायत समितियों में भाजपा से ज्यादा वोट लिए

आरएलपी के वोटों का एनालिसिस करें तो जयपुर में तीसरी राजनीतिक ताकत का प्रभाव कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा रहा। अमरसर में आरएलपी को 31.71 प्रतिशत वोट मिले, जबकि भाजपा 24.95 प्रतिशत पर रही। यहां आरएलपी ने 7 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 6 और भाजपा को 2 सीटें मिलीं।

दूदू में आरएलपी को 30.15 प्रतिशत और भाजपा को 28.21 प्रतिशत वोट मिले। फागी में आरएलपी को 25.97 प्रतिशत वोट मिले, जो भाजपा के 25.69 प्रतिशत वोट मिले। मौजमाबाद में आरएलपी का वोट शेयर 22.47 प्रतिशत और माधोराजपुरा में 20.04 प्रतिशत रहा।

महिलाओं को आरक्षण से 36 ज्यादा सीटें जीतीं

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में महिलाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रही। जिले की पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए 180 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन 216 महिलाएं निर्वाचित हुईं। यानी आरक्षण की संख्या से 36 ज्यादा महिलाओं ने जीत दर्ज की। कुल 383 निर्वाचित सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56.40 प्रतिशत है। जबकि 167 सीटों पर पुरुष रहे, जिनकी 43.60 फीसदी रही।

राहुल गांधी का भाजपा और आरएसएस पर हमला

अर्धनारीश्वर प्रतिमा की तस्वीर साझा कर साधा निशाना

- बोले, भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की समझ नहीं, दोनों संगठनों को बताया जातिवादी और पुरुषवादी

एजेंसी। नई दिल्ली



लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं में बनी भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त प्रतिमा (अर्धनारीश्वर स्वरूप) की तस्वीर साझा करते हुए दोनों संगठनों को असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी बताया। राहुल का कहना है कि इन संगठनों को भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की कोई समझ नहीं है।

राहुल ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने रविवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, 'मैं भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को जितना गहराई से समझता जा रहा हूं, यह बात उतनी ही साफ होती जा रही है। भाजपा और आरएसएस असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी हैं। उन्हें हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की बिल्कुल समझ नहीं है।' इस पोस्ट के साथ उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं में बनी भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त प्रतिमा की तस्वीर भी साझा की। इसे अर्धनारीश्वर स्वरूप के रूप में जाना जाता है।

अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का क्या अर्थ?

अर्धनारीश्वर हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त स्वरूप है। इसमें एक ही प्रतिमा में आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप दिखाया जाता है। इस स्वरूप में शिव और शक्ति को एक साथ दर्शाया गया है। राहुल गांधी ने इसी प्रतिमा की तस्वीर साझा कर अपनी बात रखी। उनके पोस्ट का संदर्भ भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में स्त्री-पुरुष के संबंधों से जुड़ा है।

राहुल गांधी के बयान पर पहले क्या विवाद हुआ था?

राहुल गांधी पिछले सप्ताह अपनी मां सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने माता-पिता के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा था कि खाने के समय पापा बैठे होते थे और उनकी गोद में मम्मा बैठी होती थीं। राहुल ने बताया कि बचपन में उन्हें यह सामान्य लगता था। लेकिन जब वह दोस्तों के घर जाते थे और उनके माता-पिता को इस तरह साथ नहीं देखते थे तो हैरान होते थे। उन्होंने दोस्तों से यह भी पूछा था कि उनकी मां उनके पिता की गोद में क्यों नहीं बैठतीं। राहुल ने आगे कहा था कि बाद में उन्होंने अपने परिवार के दो बड़े सहारों को खो दिया। पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर उनके पिता राजीव गांधी की विस्फोट में मौत हो गई।

कांग्रेस ने उनका बचाव कैसे किया?

जवाबः माता-पिता के रिश्ते पर दिए बयान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने पिछले मंगलवार को एक और पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस के समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत ने जाल बुन दिया है, जिसकी वजह से वे प्यार जाहिर नहीं कर पाते। उन्होंने कहा था कि एक सच्चे हिंदू के तौर पर उनका कर्तव्य है कि वे लोगों को इस जाल से बाहर निकालें, ताकि वे भी प्यार और अपनेपन की खूबसूरती महसूस कर सकें। अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने 'सत्यम शिवम सुंदरम' लिखा था। कांग्रेस ने भी राहुल का समर्थन करते हुए कहा था कि प्यार को छिपाने की जरूरत नहीं है, अपनापन कमजोरी नहीं है और बराबरी की शुरुआत अपने साथी को समान दर्जा देने से होती है।

एससीओ सभ्यता संवाद में जारी हुआ 'इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र'

सभी सभ्यताओं को समान सम्मान देने पर जोर



- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और अवैध तस्करी रोकने का संकल्प, पुराना किला में तीन दिवसीय मंच पर सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत की मेजबानी में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभ्यता संवाद मंच में रविवार को 'इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र' जारी किया गया। इस दस्तावेज में दुनिया की हर सभ्यता को समान सम्मान और अपनी बात रखने का बराबर अधिकार देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उसकी अवैध तस्करी रोकने की जरूरत भी बताई गई है। तीन दिवसीय इस मंच में एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में हुआ था।

आयोजन कहां हुआ और किन देशों ने हिस्सा लिया?

एससीओ का तीन दिवसीय सभ्यतागत संवाद मंच दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इसमें एससीओ के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक ने भी मंच में हिस्सा लिया। इस आयोजन के समापन के दौरान इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र को परिणाम दस्तावेज के रूप में सामने लाया गया।

क्या भारत और पाक के बीच भी कोई बातचीत हुई?

मंच में पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक की मौजूदगी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। हालांकि, उन्होंने बताया कि भोज के दौरान भारतीय पक्ष के सदस्यों की पाकिस्तानी मंत्री के साथ बातचीत हुई थी। इसके अलावा मंच के दौरान भी दोनों पक्षों के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई। इस तरह कार्यक्रम के दौरान संपर्क तो हुआ, लेकिन इसे औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं कहा गया।

इंद्रप्रस्थ घोषणापत्र में किन-किन मुद्दों पर जोर?

इस घोषणापत्र में मुख्य रूप से सभ्यताओं के बीच समानता और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। मंच में सदस्य देशों के बीच हुई चर्चा और उनके सुझावों के आधार पर यह दस्तावेज तैयार किया गया। इसमें जिन प्रमुख बातों पर जोर दिया गया, वे इस प्रकार हैं:-

- दुनिया की प्रत्येक सभ्यता को समान सम्मान और अपनी बात रखने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए।
- अलग-अलग सभ्यताओं की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- सांस्कृतिक धरोहरों की अवैध तस्करी को रोकने की जरूरत है।
- एससीओ सदस्य देशों के बीच हुई चर्चाओं और उनके सुझावों को दस्तावेज में जगह दी गई है।

बांग्लादेश में हिंसा: अवामी लीग नेताओं के घरों पर हमला, 30 मकानों में लगाई आग, 95 प्लाटून तैनात

एजेंसी। नई दिल्ली



बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। नराइल जिले के एक गांव में अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों पर हमले हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, करीब 30 घरों में आग लगा दी गई और कई मकानों व दुकानों में लूटपाट की गई। इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 'प्रोथोम आलो' के अनुसार, कालिया उपजिला के बेंदारचर गांव में शुक्रवार दोपहर शुरू हुए हमले आधी रात तक जारी रहे। निशाना बनाए गए मकानों में पूर्व सांसद बीएम कबीरुल हक मुक्ति, पूर्व मेयर मुशफिकुर रहमान लिटन और पार्टी महासचिव कृष्णपदा घोष के घर शामिल हैं।

20 से 30 मकानों में आग लगने की सूचना

अखबार के मुताबिक, रात आठ बजे दमकलकर्मियों को गांव में 20 से 30 घर जलते मिले। स्थानीय लोगों ने बीएनपी समर्थकों पर करीब 50 घरों और दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी का आरोप लगाया है। हालांकि, स्थानीय बीएनपी नेतृत्व ने आरोपों को खारिज किया है। कालिया के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद जिन्नतुल इस्लाम ने बताया कि पूर्व सांसद के घर समेत कई मकानों में तोड़फोड़ हुई और पांच-छह घरों में आग लगाई गई। उन्होंने पिछले सप्ताह मारे गए बीएनपी के दो नेताओं के रिश्तेदार और समर्थक शुक्रवार को बेंदारचर में जुटे थे। उन्होंने हत्याओं में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और अतिरिक्त बल तैनात किया।

मोटरसाइकिल जुलूस पर हमले के बाद बढ़ा तनाव

पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अल मामून सिकदर ने 'प्रोथोम आलो' को बताया कि बीएनपी नेताओं के समर्थकों ने तीन-चार घरों में तोड़फोड़ की। यह हिंसा 18 नवंबर को बीएनपी के मोटरसाइकिल जुलूस पर हुए हमले के बाद हुई, जिसमें पार्टी से जुड़े दो नेताओं की हत्या कर दी गई थी। 'प्रोथोम आलो' के मुताबिक, पटुआखाली में गुरुवार रात से शुक्रवार शाम के बीच अवामी लीग के तीन पूर्व सांसदों के घरों पर हमला हुआ। वहीं, शनिवार को पबना की बेरा नगर पालिका में बीएनपी और अवामी लीग समर्थकों के बीच झड़प हुई। 'द डेली स्टार' के अनुसार, पुलिस ने रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल कर स्थिति संभाली।

शेख हसीना की वापसी का मुद्दा बना भारत-बांग्लादेश तनाव की वजह

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी का मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है। इस महीने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग खारिज होने के बाद तनाव बढ़ा। हसीना के वकीलों ने दिसंबर में प्रस्तावित वापसी के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश मिशन से दस्तावेज मांगे थे।

अगस्त 2024 में देश छोड़कर भारत पहुंची थीं हसीना

अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और उनकी सरकार गिर गई थी। अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। उनकी वापसी की मांग पर अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी बंद सहित एक सप्ताह के विरोध प्रदर्शन किए।

आज वीआईपी आवाजाही और धार्मिक जुलूस के चलते लागू रहेंगी यातायात पाबंदियां, देखकर निकले प्लान

एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली में सोमवार को वीआईपी आवाजाही और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर निकाले जाने वाले नगर कीर्तन के चलते कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजघाट सहित मध्य और उत्तरी दिल्ली के विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। पुलिस के मुताबिक, यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

राजघाट पर वीआईपी मूवमेंट से प्रभावित होंगे कई मार्ग

महात्मा गांधी स्मृति स्थल राजघाट पर वीआईपी आवाजाही के मद्देनजर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच यातायात का नियमन किया जा सकता है। इस दौरान आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक और आईपी फ्लाईओवर के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। इसके अलावा बीएसजेड मार्ग, रिंग रोड, आसफ अली रोड और गुरु नानक चौक से रंजीत सिंह फ्लाईओवर तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास और शांतिवन चौक से निषाद राज मार्ग तक भी यातायात नियंत्रित किया जा सकता है।

नगर कीर्तन के चलते मध्य और उत्तरी दिल्ली में डायवर्जन

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व पर नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से मध्य और उत्तरी दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से यातायात प्रतिबंध लागू होंगे। प्रतिबंध जुलूस की गति और उस समय की यातायात स्थिति के अनुसार लगाए जाएंगे। नगर कीर्तन गुरुद्वारा सीस गंज साहिब, चांदनी चौक से शुरू होकर फतेहपुरी, खारी बावली, नया बाजार चौक और पीली कोठी रोड से गुजरेगा। इसके बाद जुलूस पुल मिठाई, जोरावर सिंह मार्ग, बर्फ खाना चौक, पुल बंगश मेट्रो स्टेशन और रोशनारा रोड होते हुए गुरुद्वारा नानक पियाओ साहिब पहुंचेगा।

इन इलाकों में यातायात को लेकर रहें सतर्क

नगर कीर्तन के कारण चांदनी चौक, टाउन हॉल, फतेहपुरी, खारी बावली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग और जीटी करनाल रोड पर भी यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे निर्धारित समय के दौरान जुलूस मार्ग और प्रभावित सड़कों से बचें।

'दुनिया खतरों से भरी है, सावधान रहना'

मेलानिया ने बेटे बैरन को दी डेटिंग की सलाह



- अमेरिका की प्रथम महिला बोलीं, जिंदगी की चुनौतियों में हमेशा बेटे के साथ खड़ी रहूंगी

एजेंसी। वॉशिंगटन

अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने अपने बेटे बैरन ट्रंप को डेटिंग और निजी जिंदगी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया खतरों से भरी हुई है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मेलानिया ने भरोसा दिलाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, वह हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहेंगी। 56 वर्षीय मेलानिया ट्रंप ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज में बेटे बैरन के साथ अपने रिश्ते और बातचीत को लेकर कई बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि वह 20 वर्षीय बैरन को अक्सर बाहरी दुनिया की चुनौतियों और संभावित खतरों के प्रति आगाह करती रहती हैं। मेलानिया ने कहा, ''मैं हमेशा उससे कहती हूं कि बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। इसलिए सावधान रहना।'' उनकी यह सलाह खासतौर पर डेटिंग और निजी रिश्तों के संदर्भ में सामने आई है। मेलानिया के मुताबिक, उनके और बैरन के बीच खुलकर बातचीत होती है। वह चाहती हैं कि उनका बेटा जीवन के हर फैसले को समझदारी और सतर्कता के साथ ले।

सार्वजनिक जीवन से दूर रहते हैं बैरन

बैरन ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के सबसे छोटे बेटे हैं। 20 वर्षीय बैरन अब तक काफी हद तक सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे हैं। हालांकि, मेलानिया की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में उनके पारिवारिक रिश्तों और बेटे के प्रति उनकी चिंताओं की झलक देखने को मिली है।

सिनेगॉग के पास आगजनी से टेलीग्राम हैंडलर तक पहुंची एनआईए जांच

एजेंसी। कोच्चि

कोच्चि आगजनी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोपी की कस्टडी मांगी है। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया। एजेंसी ने एर्नाकुलम मार्केट में एक सिनेगॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) के पास स्थित नर्सरी में आग लगाने के आरोपी पुथेनक्रूज़ निवासी एबिन पॉल की कस्टडी मांगी थी। एनआईए कोर्ट के जज पीके मोहनदास ने शनिवार को एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वारंट जारी किया। इसमें निर्देश दिया गया है कि एबिन पॉल को सोमवार को अदालत में पेश किया जाए। 32 वर्षीय एबिन पॉल फिलहाल त्रिशूर के वियूर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद यह पहली बार होगा, जब एनआईए उससे हिरासत में पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी इस मामले के संभावित आतंकी कनेक्शन और आरोपी के संपर्कों की गहराई से पड़ताल करना चाहती है। हाल ही में त्रिशूर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कर तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

सीएम के बंगले पर 100 करोड़ के खर्च का दावा, डीके शिवकुमार बोले, जांच कराओ, विधानसभा में हिसाब दो

एजेंसी। नई दिल्ली



कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य भाजपा प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र को मुख्यमंत्री के नए आधिकारिक आवास 'गंगा' के नवीनीकरण पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के आरोपों की जांच कराने की चुनौती दी है। शनिवार को विजयेंद्र के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह अपनी पसंद के किसी भी विधायक को जांच समिति में शामिल कर सकते हैं और आवास के नवीनीकरण पर हुए खर्च की पड़ताल करा सकते हैं।

विजयेंद्र की अध्यक्षता में बने जांच समिति

हिरियूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयेंद्र की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित की जानी चाहिए। इसमें वह अपनी पसंद के किसी भी विधायक को शामिल कर सकते हैं। यहां तक कि जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस के नेताओं को भी समिति में शामिल किया जा सकता है। शिवकुमार ने कहा कि जांच के बाद रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाए और उस पर चर्चा हो। उन्होंने विजयेंद्र को दो दिनों के भीतर अपनी पसंद की टीम गठित कर जांच कराने और विधानसभा को रिपोर्ट सौंपने की चुनौती दी।

बिना टेंडर 100 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप

दरअसल, शुक्रवार को कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पर उनके आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में 100 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता ने दावा किया कि भीषण सूखे के दौरान सरकार ने गन्ना किसानों को मुआवजा देने के लिए धन की कमी बताई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ऐतिहासिक सरकारी आवास के नवीनीकरण पर करदाताओं के 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए।

अनदेखी और सरकारी धन की बर्बादी का आरोप

विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री से किसानों के हितों की अनदेखी बंद करने और निजी सुविधाओं के लिए जनता के टैक्स का पैसा खर्च करने पर जवाब देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को राहत देने के बजाय मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर भारी रकम खर्च कर रही है। भाजपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया तो विपक्ष विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं चलने देगा।

मुस्लिम संगठन और आत्ममंथन की आवश्यकता

आवाज़ ए तसनीम

ग्रेस मुबश्शिर। मुस्लिम मज़हबी अदारों और सामाजिक संगठनों के लिए आत्मनिरीक्षण करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में मुस्लिम संगठनों का इतिहास औपनिवेशिक बंगाल से शुरू होता है। 1855में 'अंजुमन-ए-इस्लामी कलकत्ता' की स्थापना की गई थी; यह बंगाल क्षेत्र में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पहला संगठन था।

सर सैयद ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और सोच को बढ़ावा देने के लिए 1863में 'मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी' की स्थापना की। 1877में सैयद अमीर अली द्वारा कोलकाता (बंगाल प्रेसीडेंसी) में मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए 'सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन' की स्थापना की गई थी।

देवबंद स्थित मदरसे का गठन 1887में



हुआ और बाद में यह पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। बाद में कई क्षेत्रीय धार्मिक और राजनीतिक संगठन बने। 'ऑल इंडिया मुस्लिम लीग' (1906), 'मजलीस-ए-अहरार आंदोलन' (1929) और 'नदवतुल उलमा' (1894) उत्तर भारत में स्थापित प्रमुख संगठन थे।

'केरल नदवतुल मुजाहिदीन' (1921) और 'समस्त केरल जमइयत्तुल उलमा' (1926) दक्षिण भारत के प्रमुख मुस्लिम संगठन थे।

'जमीयत उलेमा-ए-हिंद': 1919में इस्लामिक विद्वानों (उलेमा) के एक प्रमुख संगठन के रूप में स्थापित, इसने भारतीय मुसलमानों को औपनिवेशिक विरोधी (स्वतंत्रता) संग्राम में शामिल करने के लिए एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।स्वतंत्र भारत में भी यह सिलसिला जारी रहा। जहाँ कई औपनिवेशिक काल के संगठन धर्मनिरपेक्ष भारत में फलते-फूलते रहे, वहीं नए संगठन भी स्थापित किए गए। हालाँकि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों की राजनीतिक लामबंदी सीमित थी, लेकिन अधिकांश संगठन धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर केंद्रित रहे।इक्कीसवीं सदी के भारत में मौलाना मौदूदी की राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह क्यों नहीं?क्या मुसलमान गैर-मुस्लिम शासन के तहत फल-फूल सकते हैं?धार्मिक संगठनों ने भरोसा और निष्ठा कायम करने के लिए सामाजिक गतिविधियों का सहारा लिया। इनमें से कई धार्मिक संगठन शैक्षणिक और परोपकारी क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदार हैं।भारत में मुस्लिम कानून पर संभावित खतरों के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने के लिए 1972 में 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' की स्थापना की गई थी।

इसके अलावा, मुसलमानों ने धर्मनिरपेक्ष मंचों पर भी खुद को संगठित किया। 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडल' और 'इंडियन सेक्युलर सोसाइटी' का नेतृत्व हामिद दलवई ने किया था। 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज़्म' की स्थापना असग़र अली इंजीनियर ने की थी। मुस्लिम संगठनों की यह सूची यहीं खत्म नहीं होती।

मुस्लिम संगठनों के सामने चुनौती: परंपरा, सुधार और आधुनिकता

आवाज़ ए तसनीम

ग्रेस मुबश्शिर। मुस्लिम समुदाय के भीतर अनुदार (कंजर्वेटिव) आवाज़ों को बढ़ावा देने वाले तंत्र (इकोसिस्टम) को चुनौती दिए जाने की ज़रूरत है।एक स्वस्थ समुदाय को केवल ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती जो परंपराओं को सुरक्षित रखें, बल्कि ऐसे मंचों की भी ज़रूरत होती है जो समकालीन वास्तविकताओं के साथ बहस, सुधार और रचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करें।लोगों को सामूहिक सामुदायिक पहचान के इर्द-गिर्द संगठित करने की ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की विरासत स्वतंत्र भारत में भी आगे बढ़ाई गई।

गणराज्य के संवैधानिक ढांचे के भीतर, राजनीतिक जुड़ाव, कानूनी कार्रवाई और सामाजिक आंदोलनों के ज़रिए द्यश्रड्डड्ड4-द्बठ्ठद् करना (पैरवी करना) तथा समुदाय के हितों को सुरक्षित करना और राज्य से मिलने वाले लाभों को अधिकतम करना, वैध तरीकों के रूप में स्थापित हुआ।



औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित कई संगठन धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) भारत में फलते-फूलते रहे, वहीं नए संगठनों का भी उदय हुआ। आज़ादी के बाद मुसलमानों की प्रत्यक्ष राजनीतिकामबंदी (मोबिलाइजेशन) अपेक्षाकृत सीमित हो जाने के कारण, कई सामुदायिक संगठनों ने अपना मुख्य ध्यान धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकारी गतिविधियों पर केंद्रित किया।

विशेष रूप से धार्मिक संगठनों ने, विश्वास कायम करने और अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए सामाजिक पहलों का इस्तेमाल किया। इनमें से कई संगठन आज भी शिक्षा, दान और सामुदायिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 1972में स्थापित ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कथित खतरों से मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा के वास्ते विभिन्न मुस्लिम संगठनों को एक साथ लाने का प्रयास किया।

इसके साथ ही, मुसलमानों ने स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष और सुधारवादी मंचों पर भी संगठनों की स्थापना की। 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडल' और 'इंडियन सेक्युलर स्पाष्द्धद्गह्व4' की शुरुआत हामिद दलवाई ने की थी, जबकि 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज़्म' की स्थापना असगर अली इंजीनियर ने की थी। यह कोई पूरी सूची नहीं है।

यह संक्षिप्त इतिहास एक बात स्पष्ट करता हैः भारत में मुसलमानों ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक विचारों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम (दायरे) का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का निर्माण और संचालन किया है।

भारत में मुस्लिम संगठनों का इतिहास औपनिवेशिक बंगाल तक जाता है। बंगाल क्षेत्र में मुस्लिम हितों की रक्षा और उन्नति करते हुए ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलकत्ता की 'अंजुमन-ए-इस्लामी' की स्थापना 1855में एक शुरुआती संगठन के रूप में की गई थी।

इमाम का चयन बेहद सोच-समझकर क्यों किया जाना चाहिए ?



आवाज़ ए तसनीम

द्बद्धअब्दुल मुईद अजहरी। इस्लाम में मस्जिद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम जीवन में मस्जिद की भूमिका ऐतिहासिक रूप से बहुत व्यापक और गहरी रही है। मस्जिद से जुड़ी अनेक मजहबी, सामाजिक और आध्यात्मिक हिकमतें हैं। यही कारण है कि मस्जिद में नमाज की इमामत करने और उससे जुड़ी दूसरी जिम्मेदारियां निभाने वाले इमाम का चयन बेहद सोच-समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

इमाम ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों को समझता होद्बउन्हें निभाने की क्षमता रखता हो। दुर्भाग्य से, आज इमामत का पेशा उन क्षेत्रों में शामिल हो गया है, जिनकी सबसे अधिक उपेक्षा की जाती है।कई मामलों में मस्जिदों की कमेटियां धार्मिक उद्देश्यों के बजाय दुनियावी हितों, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान और सार्वजनिक सम्मान को प्राथमिकता देने लगती हैं। मस्जिद कमेटियों के अध्यक्ष अक्सर अपनी आर्थिक हैसियत के आधार पर चुने जाते हैं और धीरे-धीरे खुद को धर्म का संरक्षक समझने लगते हैं। वे ऐसा इमाम चाहते हैं, जो उनकी इच्छाओं के अनुसार धर्म की व्याख्या करे। इस तरह मस्जिद की धार्मिक गतिविधियां भी कुछ लोगों की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर निर्भर हो जाती हैं।

यूसीसी पर बहस और मुस्लिम विरोध

सबसे चिंताजनक बात यह है कि कमेटियों के अनेक सदस्यों को धर्म की बुनियादी जानकारी तक नहीं होती। वे इस्लामी शिक्षाओं और फिक्ह से अच्छी तरह परिचित नहीं होते, फिर भी इमाम की नियुक्ति का फैसला उन्हीं के हाथों में होता है।नतीजा यह निकलता है कि वे किसी योग्य इमाम का चयन करने के बजाय ऐसे व्यक्ति को रख लेते हैं, जो केवल पांच वक्त की नमाज पढ़ा दे। उनके लिए इमाम एक धार्मिक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक सेवा देने वाला कर्मचारी बनकर रह जाता है।विडंबना यह है कि अनेक जगहों पर इमाम को मिलने वाला वेतन एक मजदूर की दिनभर की कमाई से भी कम होता है।

आज की एक और बड़ी समस्या यह है कि कई इमाम स्वयं भी अपने पद की वास्तविक अहमियत और जिम्मेदारियों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं होती कि इमामत कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसके साथ कौन-कौन से कर्तव्य जुड़े हुए हैं। न तो उन्हें इस संबंध में पर्याप्त जानकारी दी जाती है और न ही जरूरी प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

स्वच्छता आधा ईमान, मुसलमान अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे?

आवाज़ ए तसनीम

मुहम्मद रज़ी-उल-इस्लाम नदवी। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि भारतीय मुसलमान, जिनका मजहब साफ-सफाई को एक बुनियादी फर्ज के रूप में सिखाता है, वे उस समुदाय की छवि पर खरे नहीं उतर पाए हैं जिसका आधा ईमान ही स्वच्छता से परिभाषित होता है। विशेष रूप से उत्तर भारत के मुसलमानों ने अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में रुचि न लेने वाले लोगों की छवि बना ली है।

इस्लाम न केवल इंसान के आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है, बल्कि उसकी शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्वच्छता को भी उतना ही महत्व देता है। साफ-सफाई इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं में से एक है। एक मुसलमान के जीवन की पहचान केवल उसकी इबादत, नैतिकता और लेन-देन से ही नहीं होती, बल्कि उसकी जीवनशैली, शरीर, कपड़ों, घर और आसपास के वातावरण की पवित्रता से भी होती है। यही कारण है कि इस्लाम ने स्वच्छता को ईमान का हिस्सा घोषित किया है और लोगों को जीवन के हर पहलू में पवित्रता बनाए रखने का निर्देश दिया है।

एक तरफ मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने की पहली शर्त वजू (शरीर की शुद्धि) है, तो दूसरी तरफ समुदाय के भीतर अपने आसपास के वातावरण की साफ-सफाई को लेकर लापरवाही बरतने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस्लाम इंसान को बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की पवित्रता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया है: 'पवित्रता (पाकीज़गी) आधा ईमान है। '(सहीह मुस्लिमः 223)

इसी तरह एक अन्य हदीस में पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमायाः 'बेशक अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को



पसंद करता है। वह स्वच्छ है और स्वच्छता से प्रेम करता है। '(जामे अल-तिर्मिज़ीः 2799)

ये शिक्षाएं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि स्वच्छता केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक धार्मिक दायित्व और इस्लामी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है: 'बेशक, अल्लाह तौबा करने वालों से प्रेम करता है और खुद को पाक-साफ रखने वालों से प्रेम करता है। '(सूरह अल-बक़रहः 222)

ज़कात का भूला हुआ मक़सद

भारतीय संदर्भ में इमाम की भूमिका पहचान, धारणा और पीड़ित होने का प्रश्न

इस्लामी इबादतों में भी पवित्रता का बुनियादी स्थान है। नमाज से पहले वजू करना, विशेष अवसरों पर स्नान (ग़ुस्ल) करना और कपड़ों व इबादतगाहों की स्वच्छता यह साबित करती है कि इस्लाम स्वच्छता को मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहता है। यहां तक कि रास्ते से किसी हानिकारक वस्तु को हटाना भी नेकी (सदक़ा) का काम घोषित किया गया है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमायाः 'रास्ते से किसी तकलीफदेह चीज़ को हटाना भी एक सदक़ा (दान) है। '(सहीह अल-बुखारीः 2472, सहीह मुस्लिमः 1009)

एक ओर स्वच्छता और साफ-सफाई के संबंध में इस्लाम की ये महान शिक्षाएं हैं, तो दूसरी ओर यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कई मुसलमान इन शिक्षाओं के प्रति लापरवाह हो गए हैं। वे इबादत करते समय तो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने आसपास के वातावरण में साफ-सफाई, अनुशासन और शुद्धता की अक्सर अनदेखी करते हैं। वे अपने घरों के अंदर तो काफी हद तक सफाई रखते हैं, लेकिन गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर बहुत कम ध्यान देते हैं।

भारतीय संदर्भ में इमाम की भूमिका



आवाज़ ए तसनीम

डॉ. नसीम अख्तर। इस्लाम में नेतृत्व केवल सत्ता या अधिकार पर आधारित नहीं है; इसकी नींव बुद्धिमत्ता, विनम्रता, करुणा और उत्तरदायित्व पर टिकी है। आज के भारतीय संदर्भ में एक इमाम की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।भावी पीढ़ी के नए इमामों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करना और अधिक आवश्यक है, जो भविष्य में समाज का नेतृत्व करेंगे। एक इमाम केवल वह व्यक्ति नहीं है जो नमाज़ की अगुवाई करता है।

वह एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक, एक सलाहकार, एक मध्यस्थ और सबसे बढ़कर, समाज में इस्लामिक मूल्यों का प्रतिनिधि होता है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह दलीय राजनीति से ऊपर रहे, धर्मशास्त्र पर स्पष्ट दृष्टि रखे और इस्लामिक दर्शन में गहराई से रचा-बसा हो।

ऐसे समय में जब देश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट रहा है, इमाम स्थानीय स्तर पर समाज का मार्गदर्शन करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसमें लोगों को उनकी आस्था में दृढ़ रखते हुए राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने की क्षमता होती है।

इमाम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारियों में से एक समाज के भीतर एकता को बनाए रखना है। अल्लाह ताला फरमाता हैः 'और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और आपस में तफ़रक़ा (विभाजन) न डालो। '(सूरह आल-ए-इमरान 3:103)

इमाम की भाषा जोड़ने वाली होनी चाहिए, न कि बांटने वाली। उसे अनावश्यक रूप से फिरकेवाराना (फिरकापरस्त) विवादों, राजनीतिक शत्रुता या व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को भड़काने से बचना चाहिए।इसका अर्थ सत्य से समझौता करना नहीं है। बल्कि इसका अर्थ है समाज के व्यापक हितों की रक्षा करते हुए बुद्धिमत्ता के साथ सत्य को प्रस्तुत करना। आधुनिक दुनिया में लोग पहले से ही अनेक विभाजनों का सामना कर रहे हैं। मस्जिद एक ऐसा स्थान होनी चाहिए जहाँ दिल आपस में जुड़ें, न कि वह स्थान जहाँ मतभेदों को बढ़ावा मिले।

विश्व के अधिकांश अन्य धर्मों के पुरोहित वर्ग की तरह, इस्लाम में भी धार्मिक नेतृत्व मुख्य रूप से एक पुरुष-प्रधान अवधारणा रहा है। इमाम के शब्दों में वज़न होता है, उसका आचरण दिलों को प्रभावित करता है, और उसकी बातचीत से अक्सर यह तय होता है कि लोग स्वयं धर्म को किस रूप में देखते हैं। वह लोगों के दृष्टिकोण को गढ़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

इसलिए, एक इमाम के वक्तव्य को इस्लाम के संदेश को अलंकृत करना चाहिए, न कि अनावश्यक कठोरता या राजनीतिकरण के माध्यम से उसे विकृत करना चाहिए। एक नेता के रूप में, इमाम को सही शब्दावली और विमर्श के साथ लोगों को सशक्त बनाना चाहिए।

उसे एक ऐसा आख्यान (नैरेटिव) बनाने में मदद करनी चाहिए जो धर्म को समकालीन वास्तविकताओं के संदर्भ में प्रस्तुत करे।लोग भले ही कभी कोई खुत्बा (उपदेश) भूल जाएँ, लेकिन वे उस तरीक़े को शायद ही कभी भूलते हैं जिस तरह से एक इमाम ने उनसे बात की थी।

अरबी शब्द 'इमाम' का अर्थ नेतृत्व है। हालाँकि, इस्लाम में नेतृत्व केवल राजनीतिक सत्ता पर आधारित नहीं है। इसलिए, एक इमाम का वक्तव्य,उसका 'कलाम' संवाद का कोई साधारण रूप नहीं है। यह एक अमानत है जो या तो दिलों पर मरहम लगा सकती है या लोगों को दूर धकेल सकती है, समुदायों को जोड़ सकती है या विभाजन पैदा कर सकती है, बदलाव की प्रेरणा दे सकती है या निराशा को गहरा कर सकती है।

मुस्लिम समुदाय को अपनी प्राथमिकताओं और खर्चों पर क्यों पुनर्विचार करना चाहिए?

मस्जिद से शिक्षा तक, समाज सेवा की नई मिसाल पेश कर रहे मुसलमान आज के सामाजिक ध्रुवीकरण, वैचारिक संघर्षों और घटते धैर्य के दौर में इमाम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। समाज को केवल ऐसे विद्वानों की आवश्यकता नहीं है जो धार्मिक ग्रंथों का उद्धरण दे सकें; उसे ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो उन शिक्षाओं को ऐसी बुद्धिमत्ता में ढाल सकें जो लोगों के जीवन के साथ सामंजस्य बिठा सके।

क़ुरआन मजीद में अल्लाह ताला का हुक्म हैः 'अपने रब के रास्ते की तरफ़ हिदायत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ, और उनसे बेहतरीन तरीक़े से बहस/बातचीत करो। यह आयत इस्लामिक संवाद के प्राथमिक सिद्धांत को स्थापित करती है। एक इमाम का मिशन बहस जीतना नहीं, बल्कि दिल जीतना है। बुद्धिमत्ता के लिए श्रोताओं, उनकी परिस्थितियों, उनके संघर्षों और उनके समझ के स्तर को समझना आवश्यक है।

यूसीसी पर बहस और मुस्लिम विरोध



आवाज़ ए तसनीम

द्बद्धग्रेस मुबश्शिर। भारत का यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता - यूसीसी) के साथ संबंध जितना कानूनी रहा है, उतना ही राजनीतिक भी रहा है।हाल के वर्षों में, यूसीसी के लागू होने से तीव्र बहस और असहमति पैदा हुई है। समर्थकों का तर्क है कि अलग-अलग पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कानूनों) के होने से अनिश्चितता और संघर्ष पैदा होता है, जिससे कानूनी विवादों का समाधान करना अधिक कठिन हो जाता है।

दूसरी ओर, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक नेताओं ने इस विचार में कई कमियों की ओर इशारा किया है और इसके संभावित परिणामों को लेकर वैध चिंताएं व्यक्त की हैं।वर्ष 2025 में, उत्तराखंड संवैधानिक आकांक्षा को लागू करने योग्य कानून में बदलने वाला पहला राज्य बन गया। असम और गुजरात भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं।फिर भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र में 'भारत' का आह्वान किया गया है जो एक राष्ट्रीय आकांक्षा का संकेत देता है, लेकिन व्यवहार में पार्टी ने राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है।आलोचकों का कहना है कि परिवार और उत्तराधिकार के कानून समवर्ती सूची (कॉन्करेंट लिस्ट) के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अनुच्छेद 44 की परिकल्पना के अनुसार, किसी कोड को 'भारत के पूरे क्षेत्र में' प्रभावी बनाने के लिए, उनका तर्क है कि इसे संसद से ही शुरू होना चाहिए।उनका मानना है कि राज्य-दर-राज्य का यह बिखरा हुआ तरीका उस संवैधानिक दृष्टिकोण को पूरा नहीं करता; इसके बजाय, इससे देश भर में कानूनी विसंगति की नई परतें पैदा होने का जोखिम है।सरकार पर आलोचकों द्वारा यह आरोप भी लगाया गया है कि वह उन मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए नए कानूनों का उपयोग कर रही है जो शरिया-आधारित पर्सनल लॉ के तहत प्रथाओं का पालन करते हैं, विशेष रूप से बहुविवाह और तलाक के कुछ ऐसे रूप जो अब यूसीसी के तहत प्रतिबंधित हैं।

ज़कात का भूला हुआ मक़सद

आवाज़ ए तसनीम

द्बएच अब्दुर रकीब। ज़कात का अर्थ केवल दान के रूप में कुछ किलो अनाज, थोड़े कपड़े या कुछ रुपये बांट देना भर नहीं है।ज़कात के बारे में क़ुरआन की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक हैःइसका उद्देश्य केवल गरीबों को किसी तरह ज़िंदा रहने में मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऊपर उठाना, आत्मनिर्भर बनाना और अंततः समाज की तरक्की में योगदान देने लायक बनाना है।

ज़कात इस्लाम का तीसरा स्तंभ है और इस्लामी जीवन-दर्शन में इसका एक अनूठा स्थान है। पूरे क़ुरआन में नमाज़ कायम करने के आदेश के साथ बार-बार ज़कात अदा करने का हुक्म भी दिया गया है।यह गहरा संबंध महज़ कोई संयोग नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि इस्लाम न केवल बंदे और अल्लाह के बीच के रिश्ते की चिंता करता है, बल्कि समाज के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारियों को भी उतनी ही अहमियत देता है। इतने अधिक महत्व के बावजूद, आज मुसलमानों के बीच ज़कात सबसे कम समझे जाने वाले फ़र्ज़ (कर्तव्यों) में से एक है। जहां नमाज़, रोज़े और अन्य दिखाई देने वाली इबादतों को बढ़ावा देने में ज़बरदस्त प्रयास किए जाते हैं, वहीं ज़कात के वास्तविक उद्देश्यों और सामाजिक बदलाव में इसकी भूमिका को समझने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

इस अंतर का एक बड़ा कारण यह है कि कई मुसलमान ज़कात को केवल एक सामान्य दान (चैरिटी) के चश्मे से देखते हैं। आम समझ में, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ दे देना ही पर्याप्त मान लिया जाता है। जब तक किसी गरीब परिवार को थोड़ी-बहुत मदद मिल जाती है, लोग यह मान लेते हैं कि ज़कात का मक़सद पूरा हो गया।

हालांकि, यह सोच एक शक्तिशाली सामाजिक संस्था को महज़ एक अस्थायी राहत तंत्र तक सीमित कर देती है। सामान्य दान किसी व्यक्ति की पीड़ा को एक दिन या एक सप्ताह के लिए कम कर सकता है, लेकिन ज़कात की रचना स्थायी बदलाव लाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य केवल भूखों को खाना खिलाना नहीं है; बल्कि उन परिस्थितियों को जड़ से खत्म करना है जो लोगों को गरीबी के दलदल में फंसाए रखती हैं।

इस नासमझी के परिणाम कई मुस्लिम समाजों में साफ दिखाई देते हैं। हर साल बड़ी मात्रा में



ज़कात बांटी जाती है, फिर भी वही परिवार साल-दर-साल मदद पर निर्भर बने रहते हैं। उनकी तात्कालिक ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में शायद ही कभी कोई सुधार आता है।इसलिए, असली सवाल यह नहीं है कि ज़कात दी जा रही है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इसका इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है जिससे इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके।

क़ुरआन उन श्रेणियों के लोगों की स्पष्ट पहचान करता है जो ज़कात पाने के हकदार हैं। फिर भी इसका ज़ोर केवल वितरण पर नहीं, बल्कि न्याय, सशक्तिकरण और समाज कल्याण पर है। जब ज़कात बिना किसी योजना के बांटी जाती है, तो इसका प्रभाव सीमित रह जाता है। लेकिन जब इसका प्रबंधन समझदारी से किया जाता है, तो इसमें ज़िंदगियों को बदलने की पूरी क्षमता होती है।

कल्पना कीजिए कि एक विधवा को इतना सहारा मिले कि वह अपना एक छोटा-सा व्यवसाय शुरू कर सके। कल्पना कीजिए कि एक हुनरमंद कारीगर को आजीविका कमाने के लिए ज़रूरी औज़ार मिल जाएं। कल्पना कीजिए कि एक युवा ज़कात के फंड से व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) प्राप्त करे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसे परिणाम उन अस्थायी मददों की तुलना में ज़कात की असली रूह के कहीं अधिक करीब हैं, जो कुछ ही दिनों में खर्च होकर खत्म हो जाती हैं। ज़कात पाने वाले एक आदर्श व्यक्ति को हमेशा के लिए 'लेने वाला' ही नहीं बने रहना चाहिए। इस व्यवस्था की सफलता इसी में है कि आज का लाभार्थी कल का योगदानकर्ता (देने वाला) बन सके। एक ऐसा समाज, जिसमें कभी ज़कात लेने वाले लोग अंततः ज़कात देने वाले बन जाएं, इस संस्था की सच्ची सफलता को दर्शाता है।

इस्लामी विद्वानों ने लंबे समय से इस बात पर ज़ोर दिया है कि ज़कात के उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता से कहीं आगे तक जाते हैं। क़ुरआन और सुन्नत का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ज़कात एक साथ आध्यात्मिक, सामाजिक और सभ्यतागत,तीनों स्तरों पर काम करती है।

ज़कात का पहला उद्देश्य व्यक्ति की आत्मिक शुद्धि (तज़किया) है। दौलत का इंसान पर गहरा असर होता है। यह लालच, स्वार्थ और सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह पैदा कर सकती है। ज़कात विश्वासियों (मोमिनों) को यह सिखाकर इन बुराइयों के खिलाफ एक दवा के रूप में काम करती है कि अल्लाह ने जो अमानत उन्हें सौंपी है, उसे दूसरों के साथ बांटा जाए।क़ुरआन इस पहलू को उजागर करते हुए कहता हैः 'और जो आत्म-शुद्धि के लिए अपना माल देता है।' (क़ुरआन 92:18)

अतः देने का यह कार्य केवल दूसरे व्यक्ति की मदद करने तक सीमित नहीं है। यह देने वाले के व्यक्तित्व को बदलने के बारे में भी है। ज़कात के माध्यम से धन-दौलत पूजा की वस्तु न रहकर, अल्लाह और मानवता की सेवा करने का एक माध्यम बन जाती है।

इस विचार को क़ुरआन की एक अन्य आयत में और मज़बूती मिलती है, जहां अल्लाह पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को निर्देश देता हैः 'उनके माल में से सदक़ा (ज़कात) लो, जिसके ज़रिए तुम उन्हें पाक-साफ़ करो और उन्हें नेकी में बढ़ाओ।

उम्माह और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का समन्वय

आवाज़ ए तसनीम



आमिर सुहैल वानी। ईरान के नए आध्यात्मिक नेता, सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई ने जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को समाप्त करने वाले समझौता ज्ञापन (रूम) पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तब एक बेहद दिलचस्प बयान जारी किया। ईरानी जनता को अपने संबोधन में उन्होंने चार बार 'राष्ट्र' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल ईरानी राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए ही समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई है, भले ही उनका दृष्टिकोण इससे भिन्न था। 'राष्ट्र' शब्द पर यह जोर उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह इस व्यापक अहसास को रेखांकित करता है कि राष्ट्र के हित सर्वोपरि हैं और बाकी सब उसके बाद आते हैं।

यह संदेश आधुनिक संदर्भ में मुस्लिम राजनीतिक चेतना के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बहुलवादी लोकतंत्रों जैसे भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में रहने वाले मुसलमानों के बीच समुदाय के प्रति निष्ठा और राष्ट्र-राज्य के प्रति वफादारी के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव को देखते हुए।

एक आम धारणा यह रहती है कि मुसलमानों की पहली निष्ठा 'उम्माह' के प्रति होती है और उसके बाद ही उनके अपने राष्ट्र का नंबर आता है। ऐसे में, एक इस्लामिक देश के आध्यात्मिक नेता सैय्यद मोजतबा हुसैनी खामेनेई का यह बयान एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि वास्तविक दुनिया में मुसलमानों की प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से, 'उम्माह' की अवधारणा सातवीं शताब्दी के अरब में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम के शुरुआती दौर में उभरी थी। मदीना का शुरुआती मुस्लिम समुदाय सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं था, बल्कि साझा आस्था और आपसी जवाबदेही के इर्द-गिर्द संगठित एक सामाजिक-राजनीतिक इकाई भी था।

دنیا کے 3 سوپر پاورز کی ملاقات
ٹرمپ، شی اور پوتن، کس نے کیا پایا؟



ڈونلڈ ٹرمپ ولادیمیر پوتن اور شی جن پنگ کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے لیے پہنچے تو ان کے ایجنڈے میں شاید کوئی زیادہ واضح مطالبات نہیں تھے۔ لیکن اس تاریخی ملاقات میں ہوا کیا اور ٹرمپ کو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال یہ بھی اٹھایا جارہا ہے کہ کیا چینی صدر نے اجلاس کے دوران روسی صدر پوتن کو نظر انداز کیا؟ یاد رہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی چین کے شہر شینزین میں ایشیا پیسیفک اکنامک سربراہی اجلاس (اپیک) میں شرکت کے لیے پہنچے تو چینی صدر شی جن پنگ خود ان کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ لیکن اس سے پہلے جب روسی صدر ولادیمیر پوتن پہنچے تو ان کے استقبال کی ذمہ داری شی جن پنگ کے چیف آف سٹاف اور کمیونسٹ پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک نے نبھائی تھی۔ ہانگ کانگ کے معروف میڈیا آؤٹ لیٹ، ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ آخری بار ایک چینی سربراہ مملکت نے ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز کے قریب پہنچ کر کسی غیر ملکی رہنما کا استقبال 1959 میں کیا تھا۔ اس وقت، چین کے سپریم لیڈر، ماؤزے تنگ، سوویت رہنما نکیتا خروشیف کا استقبال کرنے کے لیے بیجنگ کے ہوائی اڈے پر پہنچے تھے حالانکہ خروشیف کا دورہ خفیہ تھا اور دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی فضا تھی۔ اخبار نے لکھا کہ لیکن اس بار، منظر بالکل مختلف تھا، جیسے ہی ٹرمپ ایئر فورس ون کی سیڑھیوں سے اترے، دنیا کی دو طاقتور ترین قوموں کے لیڈر کیمروں کے سامنے گلے ملے۔ شی جن پنگ کی طرف سے اس طرح کا عوامی محبت کا مظاہرہ انتہائی نایاب ہے۔

چند مبصرین کا ماننا ہے کہ اس ملاقات کی تصاویر اور اس سے جنم لینے والا تاثر ہی شاید اس سربراہی اجلاس کا سب سے دیرپا نتیجہ ہوں۔ بعض نے اس ملاقات کو بڑی طاقتوں کے درمیان تاریخی 'Yalta 2.0' میٹنگ بھی قرار دیا تھا جو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ، سوویت یونین اور برطانوی سربراہان مملکت یعنی بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والی ملاقات تھی۔

کیا شی نے ٹرمپ کو پوتن سے زیادہ اہمیت دی؟

کیا ٹرمپ کے استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ شی جن پنگ کے لیے پوتن سے زیادہ اہم ہو چکے ہیں، جنہیں وہ اپنا پرانا دوست کہتے ہیں؟ یوکرین کی وزارت داخلہ کے سابق مشیر اینٹون گیراشینکو نے ہوائی اڈے پر شی جن پنگ اور ٹرمپ کے گلے ملنے کی تصویر پوسٹ کی، ساتھ ہی پوتن کے استقبال کے لیے کھڑے ایک جونیئر چینی عہدیدار کی تصویر کے ساتھ لکھا پوتن کی چین میں سرعام تذلیل کی گئی۔ انھوں نے لکھا کہ روسی صدر کا استقبال چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے جنرل آفس کے سربراہ کائی چی نے کیا۔ پوتن ان کے سامنے ایسے پیش ہوئے جیسے وہ کسی ماتحت ملک کے رہنما ہوں۔ اینٹون لکھتے ہیں، 'جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپیک سربراہی اجلاس کے لیے شینزین پہنچے تو چینی صدر شی جن پنگ ذاتی طور پر ان کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ روس کے اتحادی ہونے کے باوجود پوتن کا ٹرمپ کے مقابلے میں بہت نچلے درجے کا استقبال ہوا۔

یہ بیجنگ کی طرف سے واضح اشارہ تھا کہ چین کے ساتھ تعلقات میں روس کی پوزیشن ایک ماتحت پارٹنر کی ہے۔ صرف پوتن کے طیارے کی لینڈنگ کی فوٹیج نشر کی'۔ شی جن پنگ کا ٹرمپ کا پرتپاک استقبال ظاہر کرتا ہے کہ چین واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنبھالنے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے روس کے بیورو چیف تھامس گروو نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ 'چین امریکہ کا سب سے بڑا اسٹریٹیجک حریف ہے اور اس کی معیشت روس سے بہت بڑی ہے، روس کے یوکرین پر حملے کے بعد چین نے ماسکو کو اقتصادی امداد کے ساتھ نمایاں مدد فراہم کی تھی۔ لیکن اس ملاقات نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بیجنگ اپنے ذاتی مفادات پر مبنی فیصلے نہیں کرتا'۔ تھامس نے لکھا 'سربراہی اجلاس نے پوتن کے لیے کوئی بڑا پالیسی سنگ میل حاصل نہیں کیا، لیکن اس سے اس کی سیاسی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ سربراہی اجلاس کی روس میں بہت زیادہ تشہیر کی گئی اور میڈیا کو وسیع کوریج ملی'۔ 'اس سے پوتن کو یہ ظاہر کرنے کا موقع ملا کہ اپنی کمزور پوزیشن کے باوجود، وہ سفارتی سطح پر سٹریٹیجک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے ساتھ پوتن کی تصاویر اور ٹرمپ کی عوامی طور پر روسی صدر کو گلے لگانے کی تصاویر کریملن کے لیے ایک طاقتور علامت بن گئیں۔ اس سے یہ پیغام دینے میں مدد ملی کہ روس عالمی معاملات میں اہم ہے'۔

ماہرین کیا کہتے ہیں؟

یوریشیا گروپ کے سینئر تجزیہ کار ڈومینک چیو نے امریکی اخبار دی فلاڈیلفیا انکوائرر کو بتایا کہ 'ہمیں اس پیش رفت پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے یا یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ بیجنگ ماسکو کی قیمت پر واشنگٹن کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ چین کی سفارتی حکمت عملی اس اختلاف کی بنیاد ہے'۔ ڈومینک چیو کے مطابق شی جن پنگ کا ذاتی طور پر ٹرمپ کے استقبال کے لیے پہنچنا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ چین امریکہ کے ساتھ مستحکم تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ امریکی صدر کی طرف سے دیے گئے استقبال کا جواب بھی تھا، جنھوں نے ستمبر میں جوائنٹ بیس اینڈریوز اڈے پر شی جن پنگ کا ذاتی استقبال کیا تھا۔ ڈومینک نے کہا کہ چین اور روس کے درمیان شراکت داری پہلے ہی بہت مضبوط ہے۔ شی جن پنگ اور پوتن ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور دونوں رہنما ٹرمپ سے زیادہ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ سٹیمسن سینٹر میں چائنا پروگرام کے ڈائریکٹر یون سن کا بھی خیال ہے کہ استقبالیہ میں اس فرق سے چین اور روس کے تعلقات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ اُنھوں نے کہا کہ چین کو امریکہ اور روس دونوں کی ضرورت ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر۔

امریکہ کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، جب کہ روس چین کا پارٹنر ہے۔ بروکنگز انسٹی ٹیوشن کے ایک سینئر فیلو ریان ہاس نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'شی جن پنگ نے خود کو اس پورے پروگرام کے مرکز میں رکھا۔ انھوں نے سپر پاورز کے درمیان ایک اہم کردار ادا کیا اور اس میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کی تصاویر سے شی جن پنگ کی سیاسی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی'۔ اجلاس کے بعد تینوں ممالک کی طرف سے جاری کردہ امن کے اعلامیے میں چین کے کئی دیرینہ موقف شامل تھے، جن میں اقوام متحدہ جیسے کثیر الجہتی اداروں میں اصلاحات کا مطالبہ بھی شامل تھا۔

ٹرمپ کو کیا حاصل ہوا؟

رواں ماہ کے اوائل میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو عبرتناک شکست کے بعد اس تقریب کی شان و شوکت ہی شاید وہی چیز تھی جو امریکی صدر سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایسے میں ایشیا کے اپنے تین روزہ دورے کے دوران انھوں نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی اور امریکہ، روس اور چین کے درمیان ہونے والی پہلی سہ فریقی ملاقات کی تاریخی اہمیت کا خوب لطف اٹھایا۔ ٹرمپ نے اپیک ڈنر میں اپنے نمایاں مقام اور چین پہنچنے پر شاندار استقبال کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ 'شاندار استقبال، خوبصورتی، شاندار تقریبات اور ہزاروں افراد اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کا دورہ پہلے ہی کامیاب رہا ہے۔

تاہم، اس سہ فریقی اجلاس کے بعد اب تک امریکہ کی جانب سے غیر معمولی طور پر کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ چین نے فوری طور پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں مذاکرات کی تفصیل دی گئی، جب کہ پوتن نے ملاقات کے بعد ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کی وضاحت کی۔ لیکن ٹرمپ نے بہت کم عوامی تبصرہ کیا ہے۔ اس کے بجائے انھوں نے جمعہ کو وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کا وعدہ کیا ہے۔ اس سال کے شروع میں اپنے دورہ چین کے دوران اور گذشتہ اکتوبر میں جنوبی کوریا میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن (اپیک) سربراہی اجلاس میں شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد، ٹرمپ نے واشنگٹن واپس آتے ہوئے طیارے میں میڈیا سے بات کی۔ فی الحال، وائٹ ہاؤس جمعرات کو جاری کردہ ایک مشترکہ بیان کے ذریعے اس گفتگو کا جواب دے رہا ہے۔

یہ بیان تینوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ تاہم، دستاویز زیادہ تر 'سٹریٹیجک استحکام اور بین الاقوامی سلامتی' کو یقینی بنانے کی کوششوں کے لیے مبہم حمایت فراہم کرتی ہے۔ تین طاقتور لیڈروں کی ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر عالمی مسائل پر خوش اسلوبی سے گفتگو کرنے کی ایسی تصاویر کا سامنے آنا اس بات کی یقین دہانی کر سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی تباہ کن تنازعہ نہیں ہوگا۔ لیکن 'مذاکرات' جاری رکھنے کے وعدوں اور اس اعتراف کے علاوہ کہ جوہری جنگ 'کبھی نہیں لڑنی چاہیے'، بیان بازی بہت کم اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ اور چین کے تعلقات پر کام کرنے والی بش فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈیوڈ فائرسٹین نے بتایا کہ مجموعی طور پر یہ اچھی بات ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے رہنما مختلف طریقوں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، چاہے نتائج معمولی ہی کیوں نہ ہوں۔''

صاف شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار اور سپلائی' کو فروغ دینے کی کال کا مقصد ممکنہ طور پر پوتن ہے، کیونکہ روس بین الاقوامی منڈی میں فوسل فیول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) کی مذمت کو نظر انداز کرنا مشکل تھا، جو حالیہ دنوں میں امریکی غصے کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اگر دنیا کی تین بڑی طاقتوں کے رہنما ایک بات پر متفق ہو سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے نفاذ کی کوشش کرنے والی کثیر الجہتی عالمی تنظیموں کو اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے کافی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ چین میں رہتے ہوئے ٹرمپ نے پوتن کو اپنا 'دوست' کہا۔ چینی رہنما شی جن پنگ سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کے بعد، اُنھوں نے شی جن پنگ کے ساتھ اپنے 'بہترین ذاتی تعلقات' کی بھی تعریف کی۔ لیکن واشنگٹن واپس آنے کے بعد ٹرمپ کو سیاسی ماحول کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں ان کے ایشیا کے دورے پر ملے جلے ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔

یوٹاہ سے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان کرٹس نے جمعرات کو بی بی سی کو بتایا، 'میں اس بات پر فکر مند ہوں کہ ہم جغرافیائی سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن اور شی جن پنگ ہمارے دوست نہیں ہیں۔' اُنھوں نے کہا کہ سفارت کاری اہم ہے، لیکن یہ ہمارے مخالف کون ہیں اس بارے میں وضاحت کھونے کی قیمت پر نہیں آنا چاہیے۔

☆☆☆

دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں؟



فرانس میں مہنگائی، تعلیم اور عوامی خدمات سے متعلق پالیسیوں اور نجکاری کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ بعض منچلے ان مظاہروں کو ''انقلابِ فرانس کا دوسرا ایڈیشن'' قرار دے رہے ہیں۔ یہ درست کہ انقلاب محض نعروں سے برپا نہیں ہوتے۔ ان کے لیے مخصوص حالات، عوامی تنظیم، سیاسی قیادت اور نظام میں بنیادی تبدیلی کے عوامل بھی درکار ہوتے ہیں۔ لیکن ان نعروں میں عوامی بے چینی کی شدت ضرور جھلکتی ہے۔ جب لوگوں کو محسوس ہو کہ روزمرہ زندگی مسلسل مہنگی اور تعلیم و صحت سمیت بنیادی سہولتوں تک رسائی مشکل ہو رہی ہے اور حکمران ان کے مسائل کو ترجیح نہیں دے رہے تو احتجاج محض وقتی غصے کے بجائے سیاسی نظام سے مایوسی کا اظہار بن جاتا ہے۔

البانیہ، اٹلی اور اسپین۔۔۔۔ مسائل مختلف، اضطراب مشترک

یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی عوامی احتجاج مختلف وجوہ سے جاری ہیں۔ کہیں بدعنوانی اور حکومتی طرزِ عمل پر سوال اٹھ رہے ہیں، کہیں روزگار اور اجرتوں کا مسئلہ ہے، اور کہیں نوجوانوں کے لیے رہائش کا حصول دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ ان تمام تحریکوں کو ایک ہی مقصد کے تحت چلنے والی مہم قرار دینا درست نہیں، لیکن ان میں ایک قدرِ مشترک ضرور دکھائی دیتی ہے۔ عام شہری محسوس کر رہا ہے کہ معاشی ترقی کے باوجود اس کی زندگی زیادہ محفوظ، آسان اور باعزت نہیں ہو رہی۔

جنگ کا خرچ کون اٹھا رہا ہے؟

مشرقِ وسطیٰ میں جنگ اور کشیدگی نے عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی اور تیل کی قیمتوں کے بارے میں خدشات کو بڑھایا ہے۔ ایندھن مہنگا ہو تو اس کے اثرات نقل و حمل، اشیائے خورونوش اور روزمرہ اخراجات تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے یورپ میں تقریباً ہر جگہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے اور مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے مطالبات بھی سنائی دیتے ہیں۔

فلسطین کے پرچم اور عالمی ضمیر

یورپ کے بعض مظاہروں میں فلسطینی پرچم بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ مظاہرین اپنے مقامی مسائل کو عالمی سطح پر جنگ، قبضے اور انسانی حقوق کے سوالات سے جوڑ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک فلسطین کا مسئلہ محض ایک دور دراز خطے کا تنازعہ نہیں، بلکہ انصاف، شہری حقوق اور طاقت کے استعمال سے متعلق ایک وسیع تر سوال ہے۔ البتہ ہر ملک اور ہر مظاہرے کے مطالبات یکساں نہیں۔ کہیں فلسطین مرکزی موضوع ہے، کہیں معاشی مسائل اور کہیں بدعنوانی یا عوامی خدمات۔ اس فرق کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب میں جنگ کے خاتمے، فلسطینیوں کے حقوق اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔

پاکستان... بجلی اور ایندھن کے بلوں کے خلاف آواز

ان عالمی تحریکوں کے تناظر میں پاکستان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعتِ اسلامی بجلی کے بھاری بلوں، ایندھن کی قیمتوں، تعلیم کی نجکاری اور عوام پر بڑھتے ہوئے معاشی بوجھ کے خلاف کئی ماہ سے سڑکوں اور چوراہوں پر ہے۔ پاکستان اور یورپی ملکوں کے سیاسی و معاشی حالات یقیناً مختلف ہیں، لیکن عام شہری کی شکایات میں مماثلت ہے۔ آمدنی کے مقابلے میں اخراجات بڑھ رہے ہیں، بنیادی سہولتیں مہنگی ہو رہی ہیں اور حکمرانوں سے جواب دہی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ یہ تحریکیں ایک دوسرے سے مربوط ہوں یا نہ ہوں، ان کا تقابل ایک اہم حقیقت سامنے لاتا ہے۔ عوام کے بنیادی مسائل نظریاتی اختلافات سے زیادہ فوری اور محسوس ہونے والے ہوتے ہیں۔ بجلی کا بل، روزگار، تعلیم اور خوراک کا خرچ شہری سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے یا وہ کس سیاسی نظریے کا حامی ہے۔

دہلی کا جنتر منتر... پرچے سے انتخابی شفافیت تک

بھارت میں دہلی کے جنتر منتر پر جاری دھرنے کو بھی اسی وسیع تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس احتجاج کا آغاز امتحانی پرچے کے افشا ہونے کے معاملے سے ہوا، لیکن اب اس کے گرد امتحانی نظام کی شفافیت اور حکومتی طرزِ عمل کے سوالات بھی اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ امتحانی پرچے کا افشا قابلیت، نوجوانوں کے مستقبل اور ادارہ جاتی دیانت کا مسئلہ ہے جبکہ انتخابی شفافیت عوام کے اس حق سے متعلق ہے کہ ان کے ووٹ کی گنتی، انتخابی عمل اور سیاسی نمائندگی پر اعتماد قائم رہے۔ دونوں معاملات الگ ہیں، مگر ان کے پیچھے ایک مشترک سوال موجود ہے: کیا ادارے عام شہری کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اور کیا شکایت کی صورت میں اسے قابلِ اعتماد احتساب میسر ہے؟ اگر کسی احتجاج کے شرکا کو محسوس ہو کہ ان کی شکایات نہیں سنی جا رہیں، تو مطالبات ایک محدود مسئلے سے نکل کر وسیع تر حکمرانی اور ادارہ جاتی اعتماد کے سوالات تک پہنچ سکتے ہیں۔

بنگلہ دیش۔۔۔۔ کوٹے سے حکومت کی معزولی تک

اس حوالے سے حکمرانوں کے لیے بنگلہ دیش کا تجربہ ایک اہم سبق رکھتا ہے۔ جولائی 2024ء میں وہاں طلبہ کی تحریک سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے نظام کی اصلاح کے مطالبے سے شروع ہوئی، لیکن احتجاج کے خلاف حکومتی ردِعمل، مظاہرین پر وحشیانہ تشدد، گرفتاریوں اور بڑھتی ہوئی ہلاکتوں نے بحران کو مزید شدید کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ تحریک کے مطالبات کوٹے کی اصلاح سے آگے بڑھ کر حکومتی جواب دہی اور شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے تک پہنچ گئے۔ یہی اس واقعہ کا اصل سبق ہے کہ کبھی کبھی ایک محدود اور بظاہر بے ضرر مطالبہ اُن مسائل کی علامت بن جاتا ہے جنہیں لوگ طویل عرصے سے اپنے اندر دبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب حکومت بروقت مکالمے، شفاف تحقیقات اور اصلاحات کے ذریعے ان شکایات کا ازالہ نہیں کرتی تو معاملہ ابتدائی مطالبے سے کہیں آگے نکل سکتا ہے۔

مختلف نظریات، مگر بنیادی مطالبات مشترک

فرانس سے پاکستان، البانیہ، اٹلی، اسپین، اور دہلی سے ڈھاکا تک ان واقعات میں نہ قیادت ایک ہے، نہ نظریہ، نہ سیاسی نظام اور نہ ہی نتائج یکساں ہیں۔ پھر بھی ان میں بعض مشترک مطالبات نمایاں ہیں: مہنگائی سے نجات، روزگار کے منصفانہ مواقع، معیاری تعلیم، بدعنوانی کا خاتمہ، انتخابی شفافیت، بہتر طرزِ حکمرانی اور جنگ کے بجائے امن۔ یہ مماثلت اس بات کا اعلان نہیں کہ دنیا بھر میں ایک ہی نوعیت کا انقلاب آنے والا ہے۔ البتہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ عوامی اعتماد کسی بھی سیاسی نظام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں شہریوں کو محسوس ہو کہ ان کی آواز بے اثر ہے، ادارے غیر شفاف ہیں اور حکمران جواب دہ نہیں، وہاں ناراضی بتدریج وسیع تر تحریک میں بدل سکتی ہے۔ ان مظاہروں کا انجام کیا ہوگا، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ کچھ حکومتیں اصلاحات کے ذریعے عوامی اعتماد بحال کر سکتی ہیں، کچھ محدود رعایتیں دیکر احتجاج کو ٹالنے کی کوشش کریں گی جبکہ بعض تحریکیں وقت کے ساتھ کمزور بھی پڑ سکتی ہیں۔ لیکن حکمرانوں کیلئے دانش مندی اسی میں ہے کہ وہ عوامی بے چینی کو محض وقتی شور سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ بنگلہ دیش کی مثال یاد دلاتی ہے کہ احتجاج کا آغاز کسی ایک مسئلے سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے موجود وسیع تر شکایات کو مسلسل نظر انداز کیا جائے تو سیاسی بحران کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ پیرس ہو یا لاہور، دہلی ہو یا ڈھاکہ۔۔۔۔ عوام کی زبان، مذہب اور نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن روٹی، روزگار، تعلیم، انصاف اور باعزت زندگی کی ضرورت مشترک ہے۔ حکومتوں کیلئے اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ احتجاج کتنی جلدی ختم کراتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اُن شکایات کا ازالہ کس حد تک کرتی ہیں جنہوں نے لوگوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اختلاف کو محض سیاسی مخالفت نہ سمجھیں، بلکہ اس کے اسباب کا جائزہ لیں اور شفاف تحقیقات کے ذریعے اعتماد بحال کریں۔

سمیع، سرفراز کے بعد سراج ٹیم سے باہر
سابق کپتان سریکانت کی گوتم گمبھیر پر شدید تنقید



آوازِ تسنیم: ہندوستانی کرکٹ ٹیم اس وقت نیوزی لینڈ کے خلاف ٹسٹ سیریز کھیل رہی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا ٹسٹ ویلنگٹن میں 19 نومبر سے شروع ہوا۔ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین اس وقت حیران رہ گئے جب میچ سے قبل ٹیم انڈیا کے پلیئنگ الیون کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایسی پلیئنگ الیون تھی جس نے کرکٹ کی معلومات رکھنے والوں کو پوری طرح سے حیران کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس میں ٹیم انڈیا کے بہترین فاسٹ بولر محمد سراج کا نام شامل نہیں تھا۔ سراج کا شمار اس وقت بمراہ کے بعد ٹیم انڈیا کے سب سے بہترین بولر کے طور پر ہوتا ہے۔ سراج نے متعدد مرتبہ بمراہ کی غیر موجودگی میں ٹیم کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ ہندوستان کا دورہ آسٹریلیا ہو کہ انگلینڈ سیریز حیدرآبادی میاں بھائی نے بمراہ کی غیر موجودگی میں جو کارکردگی دکھائی وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ سراج کے پاس نہ صرف رفتار بلکہ سوئنگ بھی ہے اور نیوزی لینڈ کی وکٹیں اس طرح کے بولرس کیلئے سازگار مانی جاتی ہیں۔ ایسے میں سراج کو ٹیم سے باہر رکھنا سمجھ سے باہر ہیں۔ ہندوستان کے سابق کپتانوں سنیل گواسکر، کرشنما چاری سریکانت اور روی شاستری نے بھی گوتم گمبھیر کے اس فیصلہ پر کڑی تنقید کی۔ کرشنما چادری سریکانت نے فیصلہ پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محمد سمیع، سرفراز خان اور اب محمد سراج، سب کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ سریکانت نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں اس فیصلے کے پیچھے کوئی منطق ہے؟۔ انہں و نے کہا کہ سراج نے ہندوستان کیلئے سب کچھ کیا ہے۔ وہ ہمیشہ بھرپور جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں اور ٹیم کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انہیں صرف اس وجہ سے ڈراپ کر دیا گیا کہ پچ فاسٹ بولرز کیلئے سازگار تھی۔ سریکانت نے مزید کہا کہ صرف گوتم گمبھیر ہی اس منطق کو سمجھ سکتے ہیں۔ گواسکر نے بھی ٹیم کے انتخاب کو لیکر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ سراج نے کبھی بھی اپنی کارکردگی سے مایوس نہیں کیا اس کے باوجود انہیں ٹیم سے باہر کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ روی شاستری نے کہا کہ مجھے ٹیم انڈیا کا پلیئنگ الیون دیکھ کر حیرت ہوئی کیونکہ ان 11 کھلاڑیوں ٹیم کا دوسرا سب سے بہترین بولر شامل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد سراج جیسے بہترین گیند باز کو ویلنگٹن کی وکٹ پر ہندوستان کے پلیئنگ الیون سے باہر کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔

گواسکر نے حیرت کا اظہار کیا

ویلنگٹن میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹسٹ کیلئے ٹیم انڈیا کے انتخاب نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر اور کپتان شبمن گل نے محمد سراج اور روبندر جڈیجہ جیسے مسلسل پرفارمرز کو پلیئنگ الیون سے باہر کر دیا۔ لیجنڈری سنیل گواسکر نے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا۔ انشول کمبوج اور واشنگٹن سندر نے سراج اور جڈیجہ کی جگہ پہلے ٹسٹ کیلئے پلیئنگ الیون میں شامل کیا ہے۔ ویلنگٹن کے بیسن ریزرو میں سبز پچ کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہندوستان نے پلیئنگ الیون میں چار تیز گیند بازوں کا انتخاب کیا جن میں جسپریت بمراہ انشول، پرسدکرشنا اور آکاش دیپ شامل ہیں۔ واشنگٹن سندر ٹیم کے واحد آل راؤنڈر ہیں۔ سنیل گواسکر نے سونی اسپورٹس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ سراج کو پہلے ٹسٹ میں موقع ملے گا کیونکہ وہ آخری ونڈے میں کھیل چکے ہیں۔ اس لیے ان کو موقع نہ ملنا حیران کن ہے۔ گواسکر نے زور دے کر کہا کہ وہ نہیں مانتے کہ سراج نے کبھی ہندوستان کو مایوس کیا ہے۔ سابق کپتان نے اس بات پر زور دیا کہ سراج کی فارم میں کوئی کمی نہیں ہے تاکہ ان کے ٹسٹ الیون سے اخراج کی ضمانت دی جا سکے۔ انہوں نے گزشتہ سال انگلینڈ کے دورے کے دوران سراج کی شاندار کارکردگی کو بھی یاد کیا۔ گواسکر نے کہا کہ سراج کی بولنگ میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وہ اچھی تال میں ہے۔ میں نے حال ہی میں جو بھی کرکٹ دیکھی ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کیوں منتخب نہیں کیا گیا۔ مجھے صرف امید ہے کہ منتخب کھلاڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ تاہم نیوزی لینڈ کے سابق آل راؤنڈر اسکاٹ اسٹائرس نے انشول کمبوج کے انتخاب کو درست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کمبوج تیز گیند بازوں کیلئے سازگار حالات میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسٹائرس نے نشاندہی کی کہ انشول نے حال ہی میں ختم ہونے والی ونڈے سیریز میں نیوزی لینڈ کو حیران کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جانتا ہوں کہ سراج نے ہندوستان کیلئے بہت کچھ کیا ہے۔

संपादकीय | कश्मीर में आखिरी स्थानीय आतंकी के मारे जाने का दावा

जब कोई बड़ा आतंकवादी घाटी में मारा जाता है, तब सरकार की प्रतिक्रिया आमतौर पर ऐसी होती है, मानो वहां इस समस्या का अंत हो गया है। मगर फिर कुछ समय बाद कोई आतंकी हमला यह बताने के लिए काफी होता है कि वहां अब भी इस समस्या की जटिलता में कमी नहीं आई है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मारे गए व्यक्ति को घाटी का आखिरी स्थानीय आतंकी बताया। पिछले काफी समय से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की समस्या किस स्तर पर कायम है, यह छिपा नहीं है। हर कुछ दिनों के बाद जिस तरह सुरक्षाबलों के शिविरों पर आतंकियों ने हमले जारी रखे हैं, उसमें जवान शहीद या घायल होते रहे, उससे साफ है कि राज्य में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए तमाम अभियानों में आतंकियों को खत्म करने के दावे जरूर किए गए, लेकिन हर अगली घटना यह बताती रही कि अभी वहां यह समस्या अपने जटिल स्वरूप में मौजूद है।

गौरतलब है कि आतंकियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने देवसर इलाके के जंगलपोरा गांव में खोज अभियान चलाया था। वहीं आत्मसमर्पण से इनकार करने पर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट को मुठभेड़ में मार गिराया गया। जाहिर है, समूची घाटी में आतंकवाद का जाल जिस तरह काम करता है और उसमें आए दिन सुरक्षाबलों से लेकर आम लोगों को निशाना बनाया जाता है, उसमें लतीफ भट का खात्मा एक बड़ी उपलब्धि है। अगर उसके घाटी का आखिरी स्थानीय



आतंकी होने के बारे में सरकार के दावे सही हैं, तो उसका मारा जाना इस लिहाज से भी अहम है कि सीमा पार के आतंकी संगठनों की एक बड़ी ताकत स्थानीय आबादी में फैला उनका जाल ही होता है। ऐसे में अगर लतीफ भट कश्मीर में इसी भूमिका में था, तो उसकी मौत के बाद अब आतंक के दुश्चक्र के एक मजबूत आधार को कमजोर करने में मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार बाहरी हस्तक्षेप का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब उसे स्थानीय समर्थन और संरक्षण मिलता है, तो उसकी पकड़ को ढीला करना एक चुनौती होती है। विचित्र यह है कि जब कोई बड़ा आतंकवादी घाटी में मारा जाता है, तब सरकार की प्रतिक्रिया आमतौर पर ऐसी होती है, मानो वहां इस समस्या का अंत हो गया है। मगर फिर कुछ समय बाद कोई आतंकी हमला यह बताने के लिए काफी होता है कि वहां अब भी इस समस्या की जटिलता में कमी नहीं आई है। सही है कि बीते कुछ समय से सुरक्षाबलों और स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र के बीच बेहतर तालमेल की वजह से आतंकियों के स्थानीय संजाल को कमजोर करने में मदद मिली है। बल्कि कई बार स्थानीय लोगों की ओर से भी आतंकी संगठनों का सहयोग करने से इनकार करने की खबरों ने इस समस्या का सामना करने को लेकर एक सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण किया। मगर इसके बरक्स यह भी सच है कि कुछ समय के अंतराल पर सुरक्षाबलों या उनके शिविरों पर घात लगाकर हमला करने या फिर लक्षित हमलों के तहत महज रोजी-रोटी के लिए अन्य राज्यों से वहां जाकर मजदूरी करने वाले लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं।

मनुष्य की जरूरतें भी पूरी हों और प्रकृति भी बचे

> सहानुभूति हमें दूसरों के दुख और जरूरतों को समझना सिखाती है। विनम्रता यह याद दिलाती है कि मनुष्य का ज्ञान और नियंत्रण सीमित है। मितव्ययिता हमें अपनी जरूरतों और उपभोग पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ये गुण केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध बनाने में भी मदद करते हैं। लोकतंत्र की असली शक्ति इसी साझेपन में है। जब लोग अपने आसपास की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तब समाज केवल शिकायत करने वालों की भीड़ नहीं रहता, बल्कि अपने भविष्य का निर्माण करने वाला समुदाय बनता है।

कुमार सिद्धार्थ

हम जिस दौर में जी रहे हैं, उसमें समस्याओं की कमी नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पानी का संकट, प्रदूषण, खेती पर बढ़ता दबाव और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों से अपेक्षा स्वाभाविक है, क्योंकि नीतियां बनाने, संसाधन जुटाने और बड़े स्तर पर बदलाव लाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। मगर क्या अपने जीवन और भविष्य को बेहतर बनाने की पहल हम स्वयं भी नहीं कर सकते?

स्वशासन का अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण या स्थानीय निकायों को अधिकार देना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है अपने जीवन से जुड़े फैसलों में सक्रिय भागीदारी, सामूहिक जिम्मेदारी और अपने संसाधनों के उपयोग पर समुदाय का विवेकपूर्ण नियंत्रण। लोकतंत्र तभी जीवंत होता है, जब नागरिक मतदान करने के बाद पांच साल तक दर्शक बनकर नहीं रहते, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में निरंतर भागीदारी करते हैं। विडंबना यह है कि आधुनिक विकास की चमक के बीच हमने धीरे-धीरे अपने जीवन से जुड़े अनेक फैसले बाजार, बड़ी कंपनियों और सत्ता के विभिन्न केंद्रों के हवाले कर दिए हैं। हम क्या खाएं, पानी कहां से आए, ऊर्जा की जरूरत कैसे पूरी हो और विकास के नाम पर प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इन सवालों पर स्थानीय समुदायों की आवाज अक्सर कमजोर पड़ जाती है। विकास की मौजूदा अवधारणा ने आर्थिक वृद्धि को प्रगति का पर्याय बना दिया है, लेकिन अगर इसके साथ नदियां प्रदूषित हों, भूजल नीचे जाए, जंगल सिकुड़ें और लोगों का जीवन असुरक्षित हो, तो इस प्रगति की कसौटी पर फिर से विचार करना जरूरी है।

दरअसल, हमने मान लिया है कि दुनिया जिस तरह चल रही है, उसे उसी तरह चलना है। बड़ी परियोजनाएं बनेंगी, संसाधनों का दोहन होगा और नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए कुछ योजनाएं शुरू कर दी जाएंगी। इस सोच में यह सवाल पीछे छूट जाता है कि क्या विकास का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसमें मनुष्य की जरूरतें पूरी हों, लेकिन प्रकृति की जीवनदायी क्षमता नष्ट न हो? किसी भी बदलाव की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि विकल्प संभव हैं। जब समाज यह मान लेता है कि मौजूदा व्यवस्था के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब उसकी सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसके उलट, जब लोग अपनी समस्याओं के समाधान की कल्पना करने और उन्हें व्यवहार में उतारने लगते हैं, तब बदलाव की संभावनाएं पैदा होती हैं। यह बदलाव केवल नारों और घोषणाओं से नहीं आता। इसके लिए लोगों को साथ बैठना,



संवाद करना, असहमतियों को सुनना और मिलकर काम करना पड़ता है। किसी बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल आंकड़े और तर्क पर्याप्त नहीं होते। वे समस्या की गंभीरता समझा सकते हैं, लेकिन लोगों को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखने के लिए संवेदना, कल्पनाशीलता और सामूहिक अनुभव भी जरूरी हैं। इस दृष्टि से गांवों और शहरों में होने वाली छोटी-छोटी पहलें भी महत्त्वपूर्ण हैं। किसी गांव में लोग मिलकर तालाब को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हैं, तो कोई समुदाय वर्षा जल को सहेजने की व्यवस्था करता है। ऐसी पहल लोगों के बीच सहयोग, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करती हैं। हालांकि, सामुदायिक पहल का अर्थ यह नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन, जानकारी और संस्थागत सहयोग भी चाहिए। नागरिक भागीदारी जरूरी है, लेकिन उसे सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य स्वयं को अक्सर प्रकृति का स्वामी समझता रहा है, जबकि उसका अस्तित्व मिट्टी, पानी, हवा, वनस्पतियों और असंख्य जीवों के साथ गहरे संबंधों पर निर्भर है। यह समझ जितनी सहज लगती है, आधुनिक जीवन में उतनी ही उपेक्षित दिखाई देती है। अगर हम स्वयं को जीव-जगत का हिस्सा मानें, तो विकास और समृद्धि के अर्थ भी बदलेंगे। तब सवाल केवल यह नहीं होगा कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि यह भी होगा कि हमारी जीवनशैली पृथ्वी की सीमाओं के अनुरूप है या नहीं। स्वशासन दरअसल समानता, पारदर्शिता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता भी मांगता है। अगर समुदाय के भीतर महिलाओं, वंचित समूहों और कमजोर तबकों की आवाज को जगह नहीं मिलती, तो विकेंद्रीकरण के बावजूद सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सिमट सकती है। इसलिए जरूरत ऐसी सामूहिक संस्कृति की है, जिसमें सहानुभूति, विनम्रता और मितव्ययिता को महत्व मिले।

सहानुभूति हमें दूसरों के दुख और जरूरतों को समझना सिखाती है। विनम्रता यह याद दिलाती है कि मनुष्य का ज्ञान और नियंत्रण सीमित है। मितव्ययिता हमें अपनी जरूरतों और उपभोग पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ये गुण केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध बनाने में भी मदद करते हैं।

लोकतंत्र की असली शक्ति इसी साझेपन में है। जब लोग अपने आसपास की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तब समाज केवल शिकायत करने वालों की भीड़ नहीं रहता, बल्कि अपने भविष्य का निर्माण करने वाला समुदाय बनता है। शायद यही स्वशासन का सबसे महत्त्वपूर्ण अर्थ है अपने हिस्से की दुनिया को बदलने की पहल करना और दूसरों के साथ मिलकर उसे बेहतर बनाना।

साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र
आवाज़ से पहचान तक
आवाज ए تسنیم
HINDI & URDU WEEKLY NEWS PAPER
उम्मीद की एक नई रोशनी
WWW.TASNEEMTV.COM
पॉडकास्ट कार्यक्रम
उम्मीद की एक नई रोशनी
जहाँ इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है।
आवाज़-ए-तसनीम लेकर आ रहा है एक विशेष प्रेरणादायक पॉडकास्ट कार्यक्रम "उम्मीद की एक नई रोशनी", जिसमें हम ऐसे लोगों की सच्ची कहानियाँ आपके सामने लाएँगे जिन्होंने धर्म, मज़हब, जाति और हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल कायम की है।
यह मंच उन अनसुने नायकों की आवाज़ बनेगा जिन्होंने अपने निस्वार्थ कार्यों से समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और उम्मीद की नई रोशनी जगाई है।
हर प्रेरणादायक कहानी, समाज के लिए एक नई रोशनी।
इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे
प्रेरणादायक और अनसुनी जीवन यात्राएँ
मानव सेवा और समाज परिवर्तन की कहानियाँ
सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसालें
विशेष अतिथियों के साथ प्रेरक बातचीत
समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों की दास्तान
क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है?
क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने धर्म और मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल कायम की हो?
क्या आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसने अपने कार्यों से समाज में उम्मीद की नई रोशनी जगाई हो और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो?
अगर आपके पास भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी है, तो हमसे संपर्क करें।
हो सकता है आपकी बताई हुई कहानी "उम्मीद की एक नई रोशनी" के अगले एपिसोड का हिस्सा बने और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए।
आवाज़ ए तसनीम हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र
राजस्थान के सभी जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ें
खबर, विज्ञापन एवं संवाददाता बनने के लिए संपर्क करें
02269621949 | 8946840063 | 8209508208
tasneemtv.official@gmail.com
आवाज़-ए-तसनीम पॉडकास्ट
उम्मीद की एक नई रोशनी
जहाँ इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है।
तेज़, सटीक और विश्वसनीय खबरें
आपकी आवाज़, हमारी पहचान
एक मज़बूत मीडिया, एक सशक्त समाज
हर खबर पर हमारी नज़र

देखिये
TNI आवाज़
पर हमारे खास कार्यक्रम
रमाकान्त गोस्वामी के साथ...
Tni आवाज़
आपकी आवाज़ के साथ
TNI मुलाकात
देश की जानी-मानी हस्तियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियो और समाज के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से खास बातचीत।
उम्मीद की एक नई रोशनी
संघर्ष, सफलता और प्रेरणा की ऐसी कहानियां जो बदल रही हैं समाज की सोच।
THE UNCOVERED UPDATE
हर उस खबर की पड़ताल, जो सुर्खियों के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाती है।
राजस्थान की राजनीति
राजस्थान की राजनीति, सत्ता, विपक्ष, चुनाव और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का सटीक विश्लेषण और एक्सक्लूसिव कवरेज।
रमाकान्त गोस्वामी
संस्थापक एवं प्रधान संपादक
TNI आवाज़
खबरों से आगे, सच्चाई के साथ
अब उपलब्ध 16+ प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स पर
JioTV | Jio Fiber | TATA PLAY | VI movies & tv | MXPLAYER
dailyhunt | Paytm LIVE TV | shemaroo TV | DTH LIVE TV | और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर
www.tniawaaz.com
/tniawaaz
DOWNLOAD NOW
TNI AWAAZ APP

प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजनों की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक

8 से 10 दिसंबर तक शेखावाटी हेरिटेज, सांस्कृतिक संध्या और प्रवासी राजस्थानी दिवस के होंगे विशेष आयोजन



आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। प्रवासी राजस्थानी दिवस के उपलक्ष्य में 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय विशेष आयोजनों की तैयारियों एवं रूपरेखा को लेकर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने रविवार को शासन सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इनके सुव्यवस्थित आयोजन तथा राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की।

तीन दिवसीय आयोजनों में शेखावाटी हेरिटेज, सांस्कृतिक संध्या और प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रमुख आकर्षण होंगे। यह कार्यक्रम भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के सहयोग से आयोजित किया जायेगा। इन आयोजनों के माध्यम से राजस्थान को वैश्विक निवेश, औद्योगिक साझेदारी, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

तीन दिवसीय आयोजनों की शुरुआत 8 दिसंबर को झुंझुनूं जिले के खेतड़ी स्थित अभयगढ़ में आयोजित होने वाले शेखावाटी हेरिटेज कार्यक्रम से होगी। इसके माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों, विशिष्ट स्थापत्य कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की अपार संभावनाओं को वैश्विक पहचान दिलाने पर विशेष जोर रहेगा। यह पहल क्षेत्र की विरासत को पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी क्रम में 9 दिसंबर को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में भव्य सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। इसमें राजस्थान फाउंडेशन के 25 देशों में कार्यरत अध्यक्षों का स्वागत किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को अपनी माटी, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा। तीन दिवसीय आयोजनों का प्रमुख आकर्षण 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस पर जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में आयोजित होगा। कार्यक्रम में उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, प्रवासी राजस्थानी, खनन और नगरीय विकास सहित छह प्रमुख क्षेत्रों पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में संबंधित क्षेत्रों की निवेश संभावनाओं, नीतिगत अवसरों, औद्योगिक विकास और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर चर्चा होगी। इस आयोजन में देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों के शामिल होने की संभावना है। उनकी सहभागिता से राजस्थान में औद्योगिक निवेश, व्यावसायिक साझेदारी और नए आर्थिक अवसरों को लेकर संवाद को महत्वपूर्ण मंच मिलेगा।

इन आयोजनों के जरिए राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति, पर्यटन क्षमता, औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के विकास से जोड़ने और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की विशिष्ट पहचान को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

जयपुर में पाइपलाइन ठीक करने गए कर्मचारियों को बंधक बनाया:चोर बताकर गाली-गलौज और मारपीट की, गेती से मारने की धमकी दी

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। जयपुर के पानी की पाइपलाइन ठीक करने गए कर्मचारियों को कॉलोनी के लोगों ने बंधक बना लिया। कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। गैती से मारने की धमकी दी मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। इसका वीडियो भी सामने आया है।मामला मुरलीपुरा के 4-ष्ट जमनापुरी में राजस्थान टेंट हाउस के पास का शनिवार दोपहर 3:55 बजे का है। पीड़ित ठेका कंपनी के सुपरवाइजर हंसराज रविवार को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ठेका जलकर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।

पानी की लाइन ठीक करने पहुंचे थे कर्मचारी

पुलिस ने बताया- मुरलीपुरा 4-ष्ट जमनापुरी में कई दिनों से पानी नहीं आने की शिकायत पर जलदाय विभाग के मुरलीपुरा सब-डिवीजन के अधीन फर्म गीता इंटरप्राइजेज के सुपरवाइजर हंसराज दो कर्मचारियों मुनेष और प्रेमप्रकाश के साथ पानी की लाइन ठीक करने पहुंचे थे।कर्मचारियों ने सड़क पर खुदाई कर पानी की लाइन को ठीक किया। काम पूरा होने के बाद कर्मचारी जब खोदा गया गड्ढा भर रहे थे, तभी दिनेश कोठारी, अनिल भामू और सुरेंद्र भामू सहित कुछ लोग वहां पहुंच गए।

कर्मचारियों से गाली-गलौज और मारपीट का आरोप

जयपुर जिला जलकर्मी अध्यक्ष राजपाल भार्गव ने बताया- लोगों ने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की। सुपरवाइजर हंसराज का कॉलर पकड़कर उसके साथ धक्का-मुक्की की। कर्मचारियों को चोर बताते हुए कॉलोनी में आने पर सवाल उठाए।

यूनियन ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी

घटना के विरोध में जयपुर जिला ठेका जलकर्मी यूनियन ने नाराजगी जताई है। यूनियन अध्यक्ष राजपाल शर्मा, महामंत्री जयप्रकाश, कार्यकारी अध्यक्ष हजारीलाल, प्रवक्ता कालूराम सैनी और कोषाध्यक्ष सोनूराम सैनी ने कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई।

अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान पुलिस ने जीता रजत पदक; डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने दी बधाई

बेंगलुरु में 16 से 21 नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता के मिक्स्ड डबल्स वर्ग में आईपीएस राजेंद्र सिंह सिसोदिया और वंदिता राणा की जोड़ी बनी उपविजेता

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, कैबिनेट मंत्री रिजवान और डीजीपी कर्नाटक ने प्रदान किए पदक

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। बेंगलुरु में 16 से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित ऑल इंडिया पुलिस लॉन टेनिस चैंपियनशिप-2026 में राजस्थान पुलिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। प्रतियोगिता के मिश्रित युगल (मिक्स्ड डबल्स) वर्ग में राजस्थान पुलिस के आईपीएस अधिकारी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया और वंदिता राणा की जोड़ी ने उपविजेता रहते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, टीम भावना और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राजस्थान पुलिस को गौरवान्वित किया।

प्रतियोगिता के दौरान आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री जी. परमेश्वर, कैबिनेट मंत्री श्री रिजवान तथा पुलिस महानिदेशक, कर्नाटक द्वारा पदक प्रदान किए गए।

डीजीपी ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा ने इस शानदार उपलब्धि पर आईपीएस राजेन्द्र सिंह सिसोदिया एवं वंदिता राणा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल करना राजस्थान पुलिस के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। दोनों अधिकारियों ने अपनी खेल प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और टीम भावना से प्रदेश पुलिस का गौरव बढ़ाया है।

डीजीपी श्री शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राजस्थान पुलिस का नाम रोशन करते रहेंगे।

राहुल गांधी 9 दिसंबर को आएंगे जयपुर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों का 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप; मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे उद्घाटन

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। राहुल गांधी 9 दिसंबर को जयपुर आएंगे। 30 नवंबर को जयपुर में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय सचिवों के 10 दिन के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत होगी।ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि समापन सत्र में राहुल गांधी शामिल होंगे। जयपुर ट्रेनिंग कैंप में खड़गे और राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम फाइनल किया जा चुका है।कांग्रेस के सीनियर लीडर नए राष्ट्रीय सचिवों को 10 दिन तक ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस ने 19 नवंबर को ही 81 नए राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए हैं। इसमें नए राष्ट्रीय सचिवों को राज्यों में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी है।

ट्रेनिंग कैंप की तैयारियां देखने 25 को जयपुर आएंगे केसी वेणुगोपाल

बाड़ा पदमपुरा में ट्रेनिंग कैंप के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। ट्रेनिंग कैंप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 25 नवंबर को जयपुर आएंगे।बाड़ा पदमपुरा में पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के ट्रेनिंग कैंप हो चुके बाड़ा पदमपुरा में पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के ट्रेनिंग कैंप हो चुके हैं। साल 2003 में कांग्रेस का 3 दिन का नेशनल ट्रेनिंग कैंप हुआ था। उस समय सोनिया गांधी सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रादेशिक स्तर के कई ट्रेनिंग कैंप भी यहां होते रहे हैं।

राष्ट्रीय सचिवों को संगठन से लेकर सियासत तक के गुर सिखाएंगे दिग्गज नेता

कांग्रेस में नए पदाधिकारियों को राज्यों में जिम्मेदारी संभालने से पहले ट्रेनिंग देने का नया प्रयोग शुरू किया गया है। कांग्रेस ट्रेनिंग सेल हर साल कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग कैंप लगाती रही है।इससे पहले माउंट आबू में ट्रेनिंग कैंप हुआ था। इन ट्रेनिंग कैंपों में चुनिंदा नेताओं को ही बुलाया जाता है। अन्य नेताओं को एंट्री नहीं दी जाती है। 10 दिन तक चलने वाले इस कैंप में राष्ट्रीय सचिवों को संगठन को मजबूत करने से लेकर कांग्रेस के पक्ष में सियासी नरेटिव तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

81 नए राष्ट्रीय सचिव बनाए, इनमें 6 राजस्थान से

कांग्रेस ने 19 नवंबर को 81 नए राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं, इनमें से 6 राजस्थान से हैं। राजस्थान से बनाए गए राष्ट्रीय सचिवों में हेम सिंह शेखावत, रेहाना रियाज, धीरज गुर्जर, डूंगरराम गेदर, दानिश अबरार और जगदीश जांगिड़ शामिल हैं।

जयपुर में टोल-प्लाजा पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार:अवैध पिस्टल बरामद, बिना नंबर की बोलेरो कैंपर से तोड़ा था टोल बैरियर

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। जयपुर में रिंग रोड स्थित सीतारामपुरा टोल प्लाजा पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में सांगानेर सदर थाना पुलिस और डीएसटी साउथ की टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध पिस्टल भी बरामद की हैं। वारदात में इस्तेमाल बोलेरो कैंपर गाड़ी को पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 19 नवंबर की रात सीतारामपुरा टोल प्लाजा पर बिना नंबर की बोलेरो कैंपर लेकर पहुंचे बदमाशों ने टोल बैरियर तोड़ दिया था। इसके बाद टोल कर्मचारियों को डराने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दहशत फैला दी थी।

दो आदतन अपराधियों को किया गिरफ्तार

घटना के बाद सांगानेर सदर थाना पुलिस और डीएसटी साउथ की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर को ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनराज गुर्जर उर्फ डीके गुर्जर (36) निवासी सूरजपुरा, सांगानेर सदर और बनवारी मीणा उर्फ बन्नू चांदा (24) निवासी थूणी मंगलदास, कोटखावदा के रूप में हुई है।

दोनों के पास मिली एक-एक अवैध पिस्टल

पुलिस जांच के दौरान धनराज गुर्जर की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल बरामद की गई। वहीं, उसके साथी बनवारी मीणा के कब्जे से भी एक अन्य अवैध पिस्टल मिली। पुलिस ने अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मामला दर्ज किया है।

सांगानेर सदर थाना प्रभारी कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की सूचना पर पुलिस टीम उन्हें पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर लेकर पहुंची। यहां वारदात की तस्दीक करवाई गई और मौका मुआयना किया गया। पुलिस अब आरोपियों से अन्य आपराधिक वारदातों में उनकी संलिप्तता और अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।

शेखावत बोले-पंचायत चुनावी नतीजे पार्टी के लिए आत्ममंथन का अवसर, केंद्रीय योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में कहां चूके, भाजपा करेगी आकलन

आवाज़ ए तसनीम



जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा के लिए आत्मावलोकन का अवसर बताया है। शेखावत ने कहा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद पंचायत चुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मावलोकन का अवसर है।

उन्होंने कहा कि पार्टी इस बात का आकलन करेगी कि केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ जनता तक पहुंचाने में कहां कमी रही और और सरकार के कामकाज का संदेश आम लोगों तक प्रभावी ढंग से क्यों नहीं पहुंच पाया। चुनाव परिणामों के आधार पर इन कमियों की समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा केवल प्रदेश स्तर पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर, जिला स्तर और निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर भी की जाएगी। इसके बाद जयपुर में भी इस पर विस्तृत मंथन होगा।रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा किभारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, जो चुनाव में जीत मिलने पर भी और हार होने पर भी समान रूप से परिणामों की समीक्षा करती है।शेखावत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किसी चुनावी परिणाम से निराश होकर बैठने वाले नहीं हैं। भाजपा का राजनीतिक सफर दो सीटों से शुरू होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने तक पहुंचा है। ऐसे में किसी एक चुनाव का परिणाम पार्टी के आत्मविश्वास और संकल्प को प्रभावित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए चुनावी नतीजे केवल जीत और हार का आंकड़ा नहीं होते, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे की रणनीति तैयार करने का अवसर भी मिलता है।

डबल इंजन की सरकार के बावजूद ऐसा रिजल्ट गंभीरता का विषय

शेखावत ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद पंचायत चुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं।

पुष्कर मेला 2026

रेगिस्तान के रंगों में जीवंत हो रही राजस्थान की संस्कृति और परंपरा

सजे-धजे ऊंटों और विदेशी सैलानियों के आकर्षण से गुलजार हुआ पुष्कर मेला





आवाज़ ए तसनीम

पुष्कर / जयपुर। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2026 अपने अनूठे रंगों के साथ इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 17 नवंबर से 24 नवंबर तक आयोजित हो रहे इस मेले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु और पशुपालक पहुंच रहे हैं। पुष्कर की रेतीली धरती पर सजे-धजे ऊंट, घोड़े, रंग-बिरंगी राजस्थानी पोशाकें और संगीत की गूंज यहां आने वाले लोगों को राजस्थान की असली संस्कृति से रूबरू करा रही है।

पुष्कर मेला पशुओं की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की लोक कला, परंपरा, खानपान व्यापार और धार्मिक विरासत का अनूठा संगम है। मेले में राजस्थान के अलग-अलग जिलों से पशुपालक अपने ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं के साथ पहुंच रहे हैं। ऊंटों को आकर्षक आभूषणों, रंगीन कपड़ों और पारंपरिक डिजाइनों से सजाया गया है, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। पुष्कर अपने खास खानपान के लिए भी मशहूर है। यहां रबड़ी मालपुआ, खस्ता कचौड़ी..दाल-बाटी चूरमा और ऊंटनी के दूध की चाय खासतौर पर लोगो के स्वाद का केन्द्र बनी हुई हैं.

पुष्कर सरोवर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबार को मिल रहा बढ़ावा–

मेले का धार्मिक पक्ष भी बेहद खास है। पुष्कर सरोवर के घाटों पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है। यहाँ 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। शाम के समय सरोवर के घाटों पर होने वाली महाआरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगी। पुष्कर मेले से स्थानीय व्यापारियों, हस्तशिल्प कलाकारों, होटल संचालकों और छोटे दुकानदारों को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। मेले में राजस्थानी आभूषण, पारंपरिक कपड़े, हस्तनिर्मित वस्तुएं और स्थानीय खान-पान की दुकानों पर पर्यटकों की अच्छी चहल-पहल देखने को मिल रही है।

पुष्कर मेले में करोड़ो के घोड़े की चर्चा–

पुष्कर मेले में घोड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल रेट कार्ड और लोगों के बीच हो रही चर्चाओं में कुछ घोड़ों की कीमत करोड़ो रुपये तक बताई जा रही है। इन घोड़ों की खूबसूरती और कद-काठी देखने के लिए राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं।

حدیدہ پر سعودی اتحاد کی بمباری، یمن میں فضائی کارروائیاں تیز

پانچ ڈرون اور تین بلسٹک میزائل مار گرانے کا ریاض کا دعویٰ

حوثیوں کی جدہ سمیت سعودی بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی



آوازِ تسنیم

) یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی فوجی کارروائیاں تیز ہوگئی ہیں۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے بحیرہ احمر کے ساحلی شہر حدیدہ کی بندرگاہ پر حملہ کرتے ہوئے حوثیوں کی عسکری صلاحیتوں اور اسلحہ کی مبینہ اسمگلنگ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے حوثیوں کے پانچ ڈرون اور تین بیلسٹک میزائل مار گرائے ہیں۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق، سعودی دفاعی نظام نے جمعہ کو جنوبی علاقوں کی جانب داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا ہی میں تباہ کر دیا۔ جازان کی سمت داغے گئے دو میزائل بھی روک لیے گئے، تاہم ان کا ملبہ الشقیق کے علاقے میں گرا۔ اس سے قبل ریاض اور جنوبی علاقوں کی فضائی حدود میں بھی ڈرون اور میزائل حملوں کو ناکام بنانے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ سعودی اتحاد کے مطابق حدیدہ بندرگاہ کو حوثیوں کی جانب سے اسلحہ اور بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اسی لیے وہاں فوجی کارروائی کی گئی۔ اتحاد نے صنعا، صعدہ اور تعز میں بھی حوثیوں کے عسکری ٹھکانوں اور میزائل صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا اعلان کیا ہے۔ تاہم یمن کے وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا ہے کہ حدیدہ بندرگاہ بدستور مکمل طور پر فعال ہے اور وہاں سے سامان کی آمدورفت جاری ہے۔ ادھر حوثیوں نے سعودی حملوں کے جواب میں جدہ سمیت بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع سعودی بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حدیدہ پر حملے جاری رہے تو سعودی بندرگاہیں بھی ان کے حملوں کی زد میں آسکتی ہیں۔ حوثیوں نے سعودی فضائی حدود سے گزرنے والی فضائی کمپنیوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ ممکنہ فوجی کارروائیوں کے پیش نظر احتیاط برتیں۔ یہ انتباہ ہے، ان علاقوں پر کسی نئے حملے کی تصدیق نہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سعودی اتحاد کی حدیدہ اور دیگر یمنی علاقوں میں کارروائیوں اور حوثیوں کی جوابی حملوں کی دھمکیوں نے بحیرہ احمر کے اہم بحری راستوں اور سعودی بندرگاہوں کی سلامتی سے متعلق خدشات بڑھا دیے ہیں۔

مسلمانوں کے ووٹ پر ضرب، شہریت بھی نشانے پر!

ہندوستان کو 'خصوصی تشویش' کا ملک قرار دینے امریکی کمیشن کا مطالبہ



آوازِ تسنیم

ہندوستان میں انتخابی فہرستوں پر نظرثانی کے دوران مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں میں شدت آگئی ہے۔ ملک گیر سطح پر کروڑوں ناموں کے اخراج کے اس عمل پر امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو بالخصوص انتخابی فہرستوں سے خارج کیا جارہا ہے، انہیں 'غیر ملکی' قرار دیا جارہا ہے اور اب غیر قانونی طور پر ملک بدر بھی کیا جارہا ہے۔ کلارین انڈیا ڈاٹ نیٹ کے مطابق امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (USCIRF) کے چیئرمین آصف محمود نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت مسلمانوں کو انتخابی فہرستوں سے ان کے نام خارج کرکے، انہیں غیر ملکی قرار دے کر اور اب غیر قانونی طور پر ملک بدر کرکے نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے اس صورت حال کو مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ان بیانات سے بھی جوڑا جن میں مسلمانوں کو 'دراندازٗ قرار دے کر ملک سے نکالنے کی بات کہی گئی ہے۔ واضح رہے کہ امیت شاہ نے 2 نومبر کو دعویٰ کیا تھا کہ خصوصی جامع نظرثانی (SIR) کے دوران انتخابی فہرستوں سے خارج کیے گئے تین کروڑ افراد بنگلہ دیشی دراندار تھے۔ 5 نومبر کو ہریانہ کے ایک جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی دراندازوں کی شناخت کرے گی، انہیں انتخابی فہرستوں سے خارج کرے گی اور پھر ایک ایک کرکے ملک سے باہر نکالے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، خصوصی جامع نظرثانی کے پہلے دو مراحل میں 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مسودہ انتخابی فہرستوں سے تقریباً 7.2 کروڑ نام حذف کیے گئے، جب کہ تیسرے مرحلے میں اب تک 6.16 کروڑ نام خارج ہوچکے ہیں۔ اس طرح مجموعی تعداد تقریباً 13 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، جو بھارتی انتخابی تاریخ میں رائے دہندگان کے ناموں کی سب سے بڑی حذف کاری ہے۔ اس کارروائی کا آغاز 2025 میں بہار سے ہوا تھا، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسے مزید 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں تک وسعت دی گئی۔ اب تیسرے مرحلے میں بھی یہ عمل جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق، اس حذف کاری کا غیر متناسب اثر مسلمانوں پر پڑا ہے، جو بھارت کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہیں۔ مغربی بنگال میں، جہاں نظرثانی کا عمل سب سے زیادہ آگے بڑھا، تقریباً 90 لاکھ نام حذف کیے گئے۔ کولکاتا کے سیر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، مزید جانچ کے بعد خارج کیے گئے 27 لاکھ ناموں میں تقریباً 70 فیصد مسلمانوں کے تھے، حالاں کہ ریاست کی آبادی میں ان کا تناسب 27 فیصد ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے بانی سیر احمد نے کہا کہ حکومت مخالف رجحان کے علاوہ انتخابی فہرستوں سے ناموں کی حذف کاری نے بھی مغربی بنگال کے انتخابی نتائج کے تعین میں اہم کردار ادا کیا۔ ان انتخابات میں بی جے پی نے کامیابی حاصل کرکے پہلی مرتبہ ریاست میں اقتدار سنبھالا۔ امریکی کمیشن کی تشویش کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انتخابی فہرستوں سے نام خارج کرنے کا عمل غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت اور ملک بدری کی ایک الگ مہم سے جڑتا جارہا ہے، حالاں کہ کسی شخص کا نام ووٹر لسٹ سے حذف ہوجانا اس کے غیر ملکی ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ امریکی کمیشن کے رکن جین ملز نے کہا کہ محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر بھارتی شہریوں کو ملک بدر کرنا مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی میں ایک تشویش ناک شدت کا مظہر ہے۔ انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا کہ مذہبی آزادی کی منظم اور سنگین خلاف ورزیوں کے پیش نظر بھارت کو 'خصوصی تشویش کا ملک' (Country of Particular Concern) قرار دیا جائے۔ کمیشن نے اپنی 2026 کی سالانہ رپورٹ میں بھی بھارت کو اس زمرے میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی، تاہم امریکی حکومت نے اس پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ اس معاملے پر امریکی کانگریس کی رکن پرمیلا جے پال نے بھی انتخابی فہرستوں سے تقریباً 13 کروڑ ناموں کے اخراج کی اطلاعات پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا اور پُرامن احتجاج کی حمایت کی۔

اتر پردیش میں بی جے پی کا کمل مرجھا گیا ہے

ہماری حکومت یش بھارتی سمان بحال کرے گی: اکھلیش یادو



آوازِ تسنیم: سماج وادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے اتوار کے دن وعدہ کیا کہ 2027 کے یوپی اسمبلی الیکشن کے بعد اگر ان کی پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو یش بھارتی سمان پھر سے شروع کردیا جائے گا اور اس کے تحت ماہانہ ملنے والی رقم 50 ہزار روپیے سے بڑھا کر ایک لاکھ روپیے کردی جائے گی۔ پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کی جینتی پر لکھنو میں پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان کے پتاجی جو نیتاجی کہلاتے تھے مشکل گھڑی میں ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ وہ ریاست میں یاصلاحیت لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اکھلیش نے پچھلی سماج وادی حکومت کے دوران کی گئی پہل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے طلبہ کو لیپ ٹاپ بانٹے تھے اور یش بھارتی ایوارڈس قائم کئے تھے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ سماج وادی پارٹی لکھنو کی لاء یونیورسٹی کو ملک کا ممتاز ادارہ بنانے کے لئے مناسب انفراسٹرکچر اور فنڈس فراہم کرے گی۔ سماج وادی پارٹی سربراہ نے بی جے پی کے ''رادھے رادھے کمل کھلادے'' کے نعرے پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا انتخابی نشان مرجھا گیا ہے اور اسے پھر کھلانا پڑ رہا ہے۔ اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ کے اس ریمارک کا جواب دیتے ہوئے کہ سابق میں جئے سری رام کا نعرہ لگانے سے پیچھے ہٹنے والے سماج وادی پارٹی قائدین کو اب رادھے رادھے سن کر تکلیف ہورہی ہے، اکھلیش یادو نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کیشو پرساد موریہ کو کبھی بھی اپنے بنگلہ میں مدعو نہیں کروں گا لیکن آپ (رپورٹرس) آسکتے ہیں ہم آپ کو رادھے رادھے دکھائیں گے۔ کمل کھلادے کا کیا مطلب ہے، کیا کمل مرجھا گیا ہے؟ سابق چیف منسٹر اتر پردیش نے بی جے پی پر مذہبی جذبات کے چنندہ استعمال کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کتھا کے خلاف نہیں ہے لیکن اسے ہندو دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے کئے جانے والے متنازعہ ریمارکس پر اعتراض ہے۔ سڑک حادثات کے مسئلہ پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان سڑک حادثات میں 170 ممالک سے آگے ہے۔ اتر پردیش میں سڑک حادثوں میں ہلاکتوں میں ایک سال میں 82 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ بی جے پی الیکشن نتائج کے تعلق سے اندیشہ مند ہے۔ وہ پریشان ہے کیونکہ وہ الیکشن ہارنے والی ہے۔ بنکروں کی تشویش پر انہوں نے یقین دلایا کہ سماج وادی پارٹی مقررشرح پر برقی سربراہ کرے گی جیسا کہ ان کی پچھلی حکومت میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے بی جے پی حکومت پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے قنوج کی روایتی عطر صنعت کو برباد کردیا۔ قنوج ہمارا پرفیوم سٹی ہے لیکن اسے گوبر اور گئو موتر (گائے کا پیشاب) کا شہر بنادیا گیا۔ پرفیوم بزنس کے لئے بہت بڑی عالمی مارکیٹ موجود ہے، ہم انجینئرنگ کالجس میں پرفیومری برانچ شروع کرنا چاہتے تھے۔ ہم پرفیوم میوزیم بھی قائم کرنے والے تھے لیکن یہ پراجیکٹ برباد کردیئے گئے۔

ڈگریاں قابلیتیں ہیں، پہچان نہیں: راج ناتھ سنگھ

وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آج طلبہ پر زور دیا کہ وہ خود کو ان شعبوں تک جس میں وہ نوکریاں حاصل کرتے ہیں محدود نہ رکھیں۔ ان کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی دلچسپیوں، پسند، شوق اور صلاحیتوں، قابلیتوں کی بنیاد پر کیریرس اختیار کریں۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا'' آپ کی ڈگریاں آپ کی قابلیت، آپ کی پہچان نہیں۔'' انھوں نے مزید کہا کہ طلبہ کو اپنی دلچسپیوں، شوق و ذوق کی شناخت کرنی اور اپنے خود کی راہوں کو بنانا چاہیے۔ لکھنؤ میں بابو بنارسی داس یونیورسٹی کی تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیز جیسے اے آئی سے مواقع اور نئی مہارتوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ ڈپٹی چیف منسٹر برجیش پاٹھک نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ایک ڈگری طلبہ کو ان کی پہلی ملازمت کے حصول میں مدد کرسکتی ہے، لیکن ان کی مہارتوں، پیشہ ورانہ معلومات اور قابلیت وصلاحیت ان کی پہچان اور کیریئر کے ارتقاء کا تعین کریں گے۔ فلمساز ستیہ جیت رائے نے معاشیات کی تعلیم حاصل کی، جب کہ شعبۂ انقلاب کے بانی ورگھیز کورین نے دیگر شعبوں میں خود کو منوانے سے پہلے ابتداء میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ کورین نے ہندوستان میں سفید انقلاب کی قیادت کی اور امول جیسے اداروں کے ذریعہ امداد باہمی تحریک کو مستحکم کیا۔ انھوں نے کہا کہ ان دونوں کے سفر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے تعلیمی پس منظر سے ہٹ کر بھی کامیابی حاصل کرسکتے ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ زندگی میں کبھی بھی نئی راہیں تیار کرنے میں خوفزدہ نہ ہوں۔ ان راستوں پر تنہا چلنے سے کبھی بھی پس وپیش نہ کریں۔ بالآخر آپ کی راہ میں کامیابی آئے گی۔ ابھرتی ہوئی ٹکنالوجیز خصوصاً مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے کام کی نوعیت میں تیز رفتار تبدیلیاں آرہی ہیں۔ ایسے کام جو پہلے گھنٹوں میں مکمل ہوتے تھے وہ اس اے آئی کی مدد سے منٹوں حتیٰ کہ سکنڈوں میں مکمل ہوتے ہیں۔

تلگو کمیونٹی کا چھتیس گڑھ کی اقتصادی اور صنعتی ترقی میں اہم کردار

آل انڈیا تلگو کانفرنس سے چیف منسٹر وشنو دیو سائی کا خطاب

آوازِ تسنیم: چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر وشنو دیو سائی نے کہا ہے کہ تلگو برادری نے ریاست کی اقتصادی، سماجی اور صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اپنی محنت، ٹیلنٹ اور انٹرپرینیورشپ کے ذریعے کمیونٹی نے کاروبار، تعلیم اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں ایک الگ شناخت قائم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ شری سائی ہفتہ کی رات رائے پور کے دیویندر نگر میں بالاجی ودیا مندر میں منعقد 11 ویں آل انڈیا تلگو کانفرنس 2026- سے خطاب کررہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ اور تلگو کمیونٹی کے درمیان دہائیوں پرانا رشتہ نہ صرف ثقافتی ہے بلکہ یہ رشتہ اور باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ تلگو کمیونٹی نے اپنی زبان، ثقافت اور روایات کو محفوظ رکھا ہے، چھتیس گڑھ کو اپنا کام کرنے کی جگہ بنایا ہے اور ریاست کی ترقی میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے رائے پور آندھرا ایسوسی ایشن کی 50 ویں سالگرہ پر اس کی کامیابیوں کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 5 دہائیوں کا سفر سماجی یکجہتی، ثقافتی تحفظ اور خدمت کے جذبے کی مثال ہے۔ ایسوسی ایشن نے معاشرے کو منظم کرنے اور نئی نسلوں کو اپنے ثقافتی ورثے سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلگو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے انجینئرز، منیجرس اور تکنیکی ماہرین نے ریاست کے مختلف صنعتی اداروں بشمول بھیلائی اسٹیل پلانٹ میں اہم شراکت کی ہے۔ کاروبار اور تعلیم کے شعبوں میں کمیونٹی کی فعال موجودگی ریاست کی معاشی اور سماجی ترقی کو بھی تقویت دے رہی ہے۔ چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش کے درمیان رابطے کی توسیع کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت تیار کی جارہی رائے پور-وشاکھاپٹنم سڑک دونوں ریاستوں کے درمیان سفر کو آسان بنائے گی۔ اس سے سفر کا وقت اور فاصلہ کم ہوجائے گا، اور مال برداری، تجارت اور صنعتی سرگرمیوں کو نئی تحریک ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کے رابطے میں بہتری سے دونوں ریاستوں کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔

بی جے پی 26 نومبر کو ''سمودھان گورو دیوس'' منائے گی

آوازِ تسنیم: جھارکھنڈ بی جے پی کے ریاستی جنرل سکریٹری امر کمار باؤری نے کہا کہ 26 نومبر 2026 کو بی جے پی پورے ملک میں 'سمودھان گورو دیوس' منائے گی۔ اس موقع پر جھارکھنڈ کے تمام تنظیمی اضلاع میں سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ بی جے پی ریاستی دفتر میں اتوار کو منعقدہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئین کے وقار اور جمہوریت میں اس کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے سال 2015 میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے تعاون کو مرکز میں رکھ کر سمودھان گورو دیوس منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں قرارداد بھی منظور کی گئی تھی۔ امر باؤری نے کہا کہ پہلے بابا صاحب کو صرف ان کی جینتی اور برسی پر یاد کیا جاتا تھا، لیکن اب سمودھان گورو دیوس کے ذریعے بھی ان کے خیالات اور خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا جارہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس نے آئین کے نافذ ہونے کے وقت سے ہی اس میں بار بار ترامیم کیں اور سال 1975 میں اپنا اقتدار بچانے کے لیے آئین کی بنیادی روح کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اس کے برعکس وزیر اعظم نریندر مودی نے آئین کو محفوظ رکھنے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ راجستھان کے پنچایت انتخابات میں کانگریس کو اچھی سیٹیں ملیں، لیکن پارٹی نے ای وی ایم پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بابا صاحب کو الیکشن ہرانے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی ان کے خلاف مہم چلائی تھی۔ آج وہی کانگریس بابا صاحب کے نام پر سیاست کررہی ہے۔ کانگریس کو بابا صاحب کے ساتھ کیے گئے مبینہ سلوک اور ہراسانی کے لیے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ باؤری نے کہا کہ جھارکھنڈ میں صحافیوں پر قدغن لگانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ طلبہ سڑکوں پر ہیں اور خواتین کے خلاف مظالم کے واقعات بے لگام ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس نے سمودھان گورو دیوس کے خصوصی اجلاس میں حصہ نہیں لیا اور جن جاتیہ گورو دیوس پر بحث کا بھی بائیکاٹ کیا۔ کانگریس عوام کے درمیان بھرم پھیلانے کی کوشش کررہی ہے۔ ایس آئی آر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ عمل 12 ویں بار ہورہا ہے اور کانگریس کے دورِ حکومت میں بھی 10 بار یہ عمل مکمل کیا گیا تھا۔ کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں کانگریس 20 سے 35 برسوں سے اقتدار میں نہیں ہے۔ ایسے میں ایس آئی آر کو لے کر سوالات اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس مسلسل آئینی اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کررہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا صاحب ایک ملک میں دو نشان اور دو آئین کے حامی نہیں تھے۔ ہندستان میں رہنے والے تمام لوگ ہندستانی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے 140 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کیلئے اسکیمیں تیار کی ہیں۔

ہند۔چین سرحدی مواضعات میں 5500 کروڑ کے ترقیاتی کام

آوازِ تسنیم: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ چینی سرحد کے ساتھ ساتھ واقع ارونا چل پردیش کے 40 مواضعات کے عوام اپنے آبائی مواضعات کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ مرکز کے متحرک مواضعات پروگرام (وی وی پی) کے تحت سرحدی علاقوں کو عصری سہولتوں کے ساتھ ترقی دیے جانے کے باعث یہ لوگ نقل مکانی کررہے ہیں۔ ارونا چل پردیش میں 5610 کروڑ روپئے سے زیادہ مالیت کے بڑے ترقیاتی پروگراموں کا آغاز کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت سے سرحدی مواضعات کو ملک کے پہلے مواضعات قرار دیا ہے اور ضروری سہولتیں فراہم کرتے ہوئے ان مواضعات کو ہمہ جہت ترقی دی جارہی ہے، جس میں صحت کی نگہداشت، برقی، تعلیم اور پینے کے پانی کی سربراہی بھی شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے جن پروگراموں کا آغاز کیا اُن میں ''مشن شکشت ارونا چل۔ مرحلہ II'' برقی شعبہ میں ترقی کے پراجکٹس، دیہی سڑکوں کو بہتر بنانے کے کام اور متحرک مواضعات پروگرام کے تحت 199 پراجکٹ شامل ہیں۔ ان پروگراموں کو 11 سرحدی اضلاع میں روبہ عمل لایا جارہا ہے۔ امیت شاہ نے کہا کہ وی وی پی کے ذریعہ حکومت کا مقصد ملک کے تمام سرحدی مواضعات کو ترقی دینا ہے اور عوام کی روزگار کے بہتر مواقع اور سہولتوں کی تلاش میں شہری علاقوں کو منتقلی کی روک تھام ہے۔ انھوں نے کہا کہ سرحدی مواضعات کو ترقی دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ اگر دیہی عوامی معاشی طور پر اور دیگر شعبوں میں بااختیار ہوں تو ان کے طرزِ زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ان کی خوشیوں اور مسرتوں میں اضافہ ہوگا۔ امیت شاہ نے کہا کہ ہندوستانی فوج اور انڈو۔تبتن بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کا عملہ سرحدی مواضعات کے عوام کو زرعی پیداوار میں اضافہ اور ان کی مقامی پیداوار کو بازار تک پہنچانے میں سہولت فراہم کرتے ہوئے ان کی قابل لحاظ مدد کررہا ہے۔ سابقہ کانگریس کی زیر قیادت اور مودی حکومت کے تحت کی گئی سرمایہ کاری کا تقابل کرتے ہوئے امیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ مرکز نے ارونا چل پردیش کی ہمہ جہت ترقی کیلئے چار گنا زیادہ فنڈس فراہم کیے ہیں۔

بیرون ملک اے آئی ڈاٹا سینٹرز بنانے والی امریکی کمپنیوں پر ٹرمپ کی 'بھاری ٹیکس' عائد کرنے کی دھمکی

آوازِ تسنیم: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بیرون ملک مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز تعمیر کرنے والی امریکی کمپنیوں پر "بھاری ٹیکس "عائد کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا بنیادی ڈھانچہ امریکہ کے اندر ہی تیار کیا جائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ "ہم ڈیٹا سینٹرز کو دوسرے ممالک میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے کیونکہ چین ان سب پر قبضہ کرلے گا اور ہم ان کمپنیوں پر زبردست جرمانے عائد کریں گے جو ایسا کرنے کی کوشش کریں گی۔ "اپنے دورہ ایشیا سے واپسی کے بعد ایک پریس بریفنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے مجوزہ پالیسی یا اس کے نفاذ کے طریقہ کار کی تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ "ہم یہ سب کچھ اسی ملک میں رکھنے جارہے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ "ہم اپنی کمپنیوں کو اپنے ملک سے باہر ڈیٹا سینٹرز بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔" اس ممکنہ اقدام کے بارے میں بہت کم تفصیلات فراہم کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ ان کی کابینہ کے کچھ ارکان اس بارے میں پہلی بار سن رہے ہیں۔ ٹرمپ کے یہ بیانات امریکہ میں اے آئی انفراسٹرکچر کی تیزی سے توسیع پر بڑھتی ہوئی سیاسی بحث میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر ایک اہم مسئلے کے طور پر ابھری، جہاں کئی ڈیموکریٹک امیدواروں نے توانائی کی کھپت، بجلی کی لاگت اور مقامی کمیونٹیز پر پڑنے والے اثرات کے خدشات کے پیش نظر سخت قوانین بنانے کا عہد کیا۔ میٹا اور گوگل سمیت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے مصنوعی ذہانت کی خدمات کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کو وسعت دیتے ہوئے بیرون ملک ڈیٹا سینٹرز تیار کرنے کے معاہدے کیے ہیں۔ ٹرمپ کے یہ تبصرے ایک ایسے وقت میں بھی سامنے آئے ہیں جب واشنگٹن اور بیجنگ تکنیکی برتری کے لیے مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی کارروائیوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے منسلک خطرات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے جمعہ کے روز کہا کہ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اے آئی سے متعلق فوجی فیصلوں بشمول بڑی فوجی کارروائیوں میں انسانی شمولیت لازمی ہونی چاہیے۔ چین کے شہر شینزین میں ٹرمپ کی شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد ایک میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے بیسنٹ نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکی صدر کے دورہ ایشیا کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس ٹیکنالوجی کے لیے ترجیحی اصطلاح "سپر انٹیلی جنس " کا حوالہ دیتے ہوئے بیسنٹ نے کہا کہ "میرے خیال میں یہ بہت اہم تھا کہ صدر ٹرمپ اور صدر شی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اے آئی کے ذریعے کیے جانے والے کسی بھی فوجی فیصلے میں انسانوں کو ہمیشہ شامل ہونا چاہیے اور بڑی فوجی کارروائیوں کے لیے اے آئی کو خود مختار ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے ۔"انہوں نے کہا کہ فوجی استعمال کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر ہونے والا یہ معاہدہ اے آئی کی بالادستی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر مسابقت سے متاثر نہیں ہوگا۔ بیسنٹ نے یہ بھی کہا کہ امریکی اے آئی لیبارٹریز کو اپنی تکنیکی برتری برقرار رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان خطرناک چینی اے آئی ماڈلز کا مقابلہ کیا جاسکے جو سائبر حملوں میں استعمال ہورہے ہیں۔ اے آئی چپس کی برآمدات کے حوالے سے بیسنٹ نے کہا کہ پابندیوں پر ٹرمپ کے سخت موقف کے بعد، این ویڈیا کی ایچ 200 چپ اب بھی سب سے جدید ٹیکنالوجی ہے جسے چین لائسنس یافتہ خریداری کے ذریعے حاصل کرسکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایچ 200 کے لیے چینی آرڈرز محدود رہے ہیں کیونکہ بیجنگ اپنی سیمی کنڈکٹر صلاحیتیں تیار کرنے کی کوشش کررہا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ چین ممکنہ طور پر اس شعبے میں کئی سال پیچھے ہے۔ محکمہ تجارت نے جدید اے آئی چپس تک چین کی رسائی کو مزید محدود کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں، جن میں بیرون ملک ڈیٹا سینٹرز میں استعمال ہونے والی چپس بھی شامل ہیں جہاں چینی ادارے کمپیوٹنگ کی صلاحیت کرائے پر لے سکتے ہیں۔

☆☆☆

▶ भारत के प्रति नेपाल का रुख फिर सकारात्मक होता दिखा

चीन को झटका दे भारत पहुंचे नेपाल के पीएम बालेन शाह, मोदी से मिलेंगे

- द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए बालेंद्र शाह ने चीन के बजाय भारत को चुना
- पीएम पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा

दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया शाह का गर्मजोशी से स्वागत

● नई दिल्ली

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार शाम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। मार्च में पीएम पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बालेन शाह भारत आए हैं। उनकी यह यात्रा सोमवार को समाप्त होगी और कुल मिलाकर एक दिन से कुछ अधिक समय तक चलेगी।

पीएम शाह के राजधानी दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम शाह से मुलाकात की। नेपाली पीएम बालेन शाह का भारत दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए चीन के बजाय भारत को चुना है। दरअसल, पिछले कुछ समय से नेपाल चीन के करीब जाता दिखाई दे रहा था।



34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया

बालेन शाह नेपाल एयरलाइंस की रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट से भारत पहुंचे हैं। उनके साथ 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें उनके मुख्य सलाहकार कुमार ब्यानजंकर, वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल शामिल हैं। पीएम के प्रतिनिधिमंडल के साथ कारोबारियों का एक अलग दल भी भारत आया है। भारत दौरे के दौरान बालेन शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुमु से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नेपाल के प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने दौरे से पहले इसकी जानकारी दी थी।

अयोध्या-जनकपुर के बीच शुरू होगी सीधी रेल सेवा

पीम नरेन्द्र मोदी और नेपाल के उनके समकक्ष बालेंद्र शाह सोमवार (23 नवंबर) को अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, पीए मोदी और बालेंद्र शाह दिल्ली से डिजिटल माध्यम से ट्रेन को रवाना करेंगे।

ट्रेड, ऊर्जा, निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा

दोनों देशों में होने वाली वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। खासतौर पर व्यापार, ट्रांजिट, ऊर्जा, निवेश और सीमा पार संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान ऊर्जा सहयोग से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा सकता है। कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखे जाने की तैयारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास से जुड़े कई एमओयू का आदान-प्रदान भी होना है।

बालेन शाह का दौरा क्यों है खास

बालेन शाह मार्च में नेपाल का पीएम बनने के बाद पहली बार भारत के द्विपक्षीय दौरे पर आए हैं। सितंबर में वह यूएनजीए की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन वह उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी। शाह की अगुवाई वाली आरएसपी की सरकार का गठन पिछले साल सितंबर में केपी शर्मा ओली सरकार को सत्ता से हटाने वाले युवा पीढ़ी के आंदोलन के करीब 6 महीने बाद हुआ था। मोदी ने सरकार बनने के समय ही उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। नेपाल के नए प्रधानमंत्रियों के लिए पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भारत से शुरू करना लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है। हालांकि, यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। 2024 में केपी शर्मा ओली ने इस परंपरा से अलग हटकर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना था।

भारत की सभ्यता और भाषाई विविधता के मुरीद हुए पुतिन



नई दिल्ली, आरएनएन। भारत में कदम-कदम पर भाषा बदल जाती है। कहीं हिंदी सुनाई देती है, कहीं तमिल, बंगाली, मराठी या कोई दूसरी भाषा। यहां हर इलाके की अपनी बोली, अपनी पहचान है। भारत की यही खासियत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी हैरान कर गई।

उन्होंने भारतीय सभ्यता की तारीफ करते हुए यहां की भाषाई विविधता को सिम्पली अमेजिंग यानी बेहद अद्भुत बताया। सर्बियाई फिल्म निर्देशक एमिर कुस्तुरिका को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने एमिर कुस्तुरिका को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई हालिया बातचीत का जिक्र किया। भारत की आबादी करीब 150 करोड़ है। इनमें लगभग 60 करोड़ लोग एक प्रमुख भाषा बोलते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी-अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं।

इतनी बड़ी आबादी के बीच भाषाओं की यह विविधता वाकई हैरान करने वाली है। पुतिन ने सिर्फ भारत की भाषाओं की बात नहीं की, बल्कि यहां की प्राचीन सभ्यता का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता को खास बताया। पीएम मोदी से मिली जानकारी ने उन्हें भारत को समझने का नजरिया दिया। भारत की विविधता का जिक्र करते हुए पुतिन ने रूसी सभ्यता की खासियत भी बताई। रूस में अलग-अलग समुदायों और जातीय समूहों को अपने धर्म, भाषाएं और आध्यात्मिक पहचान बचाए रखने का मौका मिला है।

पाक मंत्री बोले, आतंकवाद पर भारत सबूत दे, हम भी देंगे...

भारत- पाक के बीच पारदर्शी वार्ता की वकालत

● नई दिल्ली

भारत दौरे पर आए पाक के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने आतंकवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और पाक के बीच आतंकवाद को लेकर होने वाली किसी भी चर्चा का आधार सबूत होने चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के बीच पारदर्शी वार्ता की वकालत करते हुए कहा कि भारत अपने सबूत रखे और पाकिस्तान भी अपने सबूत पेश करेगा। पाक के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने कहा कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर किसी भी तरह की वार्ता तथ्यों और सबूतों के आधार पर होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस मामले को केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय पारदर्शी तरीके से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे एक-दूसरे के सामने अपने सबूत और तथ्य रख सकें। उन्होंने कहा कि इस आधार पर हर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है और क्षेत्र में आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने का रास्ता निकाला जा सकता है। मुसादिक मसूद मलिक ने आतंकवाद को पूरे क्षेत्र की गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के हजारों नागरिक भी चरमपंथ और आतंकवाद का शिकार हुए हैं।

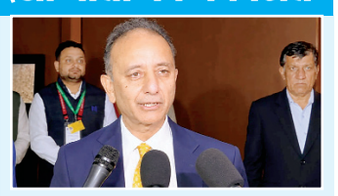

वार्ता के सवाल पर बोले- पहले न्योता तो दीजिए

भारत के साथ वार्ता को लेकर पूछे गए सवाल पर पाक मंत्री ने कहा कि जब भारत उन्हें द्विपक्षीय चर्चा के लिए आमंत्रित करेगा, तब वह वार्ता के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे उन खास मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाइए। पहले निमंत्रण दीजिए और बताइए कि आप द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं। मैं चर्चा के लिए आऊंगा और आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। पाक के संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।

2300 भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था पाक पहुंचा

लाहौर, आरएनएन। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 557वें प्रकाशपर्व में शामिल होने के लिए करीब 2,300 भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था रविवार को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान आया। अधिकारी ने बताया कि सीमा पर तीर्थयात्रियों का स्वागत इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के चेयरमैन कमर जमान, पंजाब के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) के अध्यक्ष सरदार रमेश सिंह अरोड़ा तथा अन्य अधिकारियों ने किया। ईटीपीबी के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि लगभग 2,339 भारतीय तीर्थयात्री लाहौर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पाक सरकार ने इस मौके के लिए 3,000 से अधिक वीजा जारी किए थे। हाशमी ने बताया कि श्रद्धालु पक में कई ऐतिहासिक सिख तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे, जिनमें करतारपुर साहिब भी शामिल है, और एक दिसंबर को भारत लौटेंगे।

ब्रीफ न्यूज

कनाडा : लिबरल पार्टी के नेता बने नवदीप बैंस

टोरंटो, आरएनएन। भारतीय मूल के पूर्व कनाडाई मंत्री नवदीप बैंस को ओंटारियो में लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया है। उन्होंने अगले चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया है। बैंस (49) को पार्टी के नेतृत्व सम्मेलन में तीसरे और अंतिम दौर के मतदान में 50.3 प्रतिशत वोट मिले। उन्होंने कहा कि यह भले ही नेतृत्व की दौड़ का अंत हो, लेकिन डग फोर्ड और ओंटारियो की (प्रोग्रेसिव) कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से हटाने के हमारे अभियान की यह महज शुरुआत है।

भारत-बांग्लादेश के बीच दो दिवसीय बैठक शुरू

ढाका, आरएनएन। 1996 की गंगा वॉटर ट्रिटी के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु भारत-बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग की दो दिवसीय बैठक रविवार से शुरू हुई। आगामी 12 दिसंबर को 30 साल की अवधि पूरी करते हुए यह डील समाप्त होनी है। बैठक में मौजूदा जल बंटवारा व्यवस्था और नदी के प्रवाह से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान पर चर्चा हेतु 6 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेआरसी सदस्य मो. अनवर कादिर कर रहे हैं।

लीबिया : रूसी जहाज पर यूक्रेनी समुद्री ड्रोन से हमला

काहिरा, आरएनएन। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में रविवार तड़के एक रूसी जहाज पर यूक्रेनी समुद्री ड्रोन ने निशाना बनाया। यह हमला पूर्वी लीबिया के बेंगाजी स्थित नौसैनिक अड्डे पर हुआ। हमले के बाद जोरदार विस्फोट हुआ और जहाज में आग लग गई। लीबिया के पूर्वी हिस्से की सरकार ने इस घटना की जानकारी दी है। रूसी जहाज रूस और पूर्वी लीबिया की सरकार के बीच हुए सहयोग समझौते के तहत नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा था।

ट्रम्प बोले- हम डेटा सेंटरों को दूसरे देशों में नहीं जाने देंगे

● वाशिंगटन / आरएनएन

यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विदेशों में एआई डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि इस तरह का बुनियादी ढांचा यूएस के भीतर ही विकसित हों।

ट्रम्प ने कहा कि हम डेटा सेंटरों को दूसरे देशों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि चीन इन सबको हथिया लेगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां ऐसा करने की कोशिश करेंगी, उन पर हम भारी जुर्माना लगाएंगे। ट्रम्प ने एशिया यात्रा से लौटने के बाद कहा कि हम इन सबको अपने ही देश में रखेंगे। हम अपनी कंपनियों को देश के बाहर डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रम्प ने इस संभावित कदम के बारे में ज्यादा जानकारी न देते हुए बताया कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने भी इसके बारे में पहली बार सुना है। ट्रम्प का यह बयान यूएस में एआई के बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और बढ़ाते हैं।

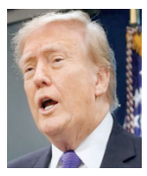

चीन इन सबको हथियाने की कोशिश में लगा

जीवाश्म ईंधन का उल्लेख न होने पर कॉप-31 डील खारिज

कॉप-31 डील : ब्रिटेन-ईयू ने प्रस्तावित डील को जलवायु के भविष्य के लिए बताया अस्वीकार्य

● अंताल्या

यूरोपीय संघ (ईयू), ब्रिटेन और विकासशील देशों के सहयोगियों ने रविवार को कॉप-31 डील को जलवायु के भविष्य के लिए अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। अंग्रेजी दैनिक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि तुर्किए में संयुक्त राष्ट्र के कॉप-31 क्लाइमेट चेंज की वार्ता का इस तरह नाटकीय समापन हुआ, जिसमें प्रस्तावित समझौते में जीवाश्म ईंधन का उल्लेख तक नहीं था।

ईयू की ओर से आयरलैंड के पर्यावरण मंत्री डैराघ ओ'ब्रायन ने कहा कि प्रस्तावित समझौता मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे फैसले का समर्थन नहीं करेंगे, जो विज्ञान के अनुरूप न हो और वैश्विक प्रतिबद्धताओं तथा आवश्यक कार्रवाई के बीच की खाई को और गहरा करने का जोखिम पैदा करे। इसमें जीवाश्म ईंधन का उल्लेख तक नहीं है। शुक्रवार को समाप्त होने वाली वार्ता रविवार दोपहर तक खिंच गई। इस दौरान स्पष्ट हो गया कि सम्मेलन की तुर्किए और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त अध्यक्षताओं की ओर से तैयार किया गया अंताल्या डील पारित होने के लिए आवश्यक सर्वसम्मति हासिल नहीं कर पाएगा।

अंताल्या समझौते में देशों से अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विद्युतीकरण करने का आह्वान किया गया था। इसमें अमीर देशों से जलवायु संकट के प्रभावों के अनुकूल ढलने में गरीब देशों की मदद के लिए वित्तीय सहायता देने और पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के संभावित अतिक्रमण को न्यूनतम रखने की अपील भी की गई थी। समझौते में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की उस प्रक्रिया का समर्थन नहीं किया गया, जिसकी मांग 130 से अधिक देशों ने की थी।



भारत ने कहा, जलवायु वित्त का मुद्दा पूरी तरह दम तोड़ चुका है

तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में रविवार को कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका। इसके बाद समान सोच वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत ने कहा कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न वार्ता सत्रों में जलवायु वित्त के मुद्दे पर बातचीत करने से इनकार किया गया। एलएमडीसी की ओर से बयान देते हुए भारत ने कहा कि हमें बताया गया कि जिस समस्या को हमने पैदा नहीं किया है, उसके कारण विकासशील देशों की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, इसके बावजूद उन्हें विकसित देश के साझेदारों से जलवायु वित्त के मुद्दे पर वार्ता करने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा पहले ही पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सीओपी31 वार्षिक सम्मेलन जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की मजबूत प्रतिबद्धता और जलवायु वित्त के लिए नई एवं मात्रात्मक रूप से निर्धारित प्रतिबद्धताएं हासिल करने के मुद्दों पर मतभेदों के कारण किसी अंतिम समझौते के बिना समाप्त हो गया।

दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा

सोल, आरएनएन। द. कोरिया के शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिन ने देश में परीक्षा नकल विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेकर रविवार को पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने स्वीकार किया है।

विवाद वार्षिक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में एआई की मदद से होने वाली नकल को रोकने अंतिम समय में उठाए कदमों और उससे पैदा हुई भ्रम की स्थिति के कारण गहराया। दरअसल, अप्रैल में हुई राष्ट्रीय कर लेखा परीक्षा के टॉपर हान वोन-सियोक (34) ने 160 में से 159 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बाद एक वीडियो संदेश में स्वीकार किया था कि उसने माइक्रो-कैमरा, स्मार्टफोन और एआई उपकरणों के जरिए नकल की थी।



परीक्षा में नकल विवाद

इजराइल: नई सरकार की तेज हुई कवायद

आइजनकोट ने नेतन्याहू की पार्टी को वार्ता को बुलाया

● येरूशलम / आरएनएन

इजराइल के पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को गठबंधन पर नई वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस कदम से एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनने का रास्ता साफ हो सकता है। वार्ता जल्द शुरू होनी है।



आइजनकोट के सामने दिसंबर तक की समय-सीमा है, जिसके भीतर उन्हें संसद में इतना समर्थन जुटाना होगा कि वे नेतन्याहू की जगह ले सकें।

लिकुड पार्टी की मांग- आइजेनकोट का गुट अपने विधायी एजेंडे को रोक दे

वार्ता के दौरान बड़े कदम उठाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दोनों पार्टियों के बीच पिछले रविवार को हुई वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं कि वे एकता सरकार बनाने के लिए कितने गंभीर हैं। लिकुड ने मांग की है कि आइजेनकोट का गुट अपने विधायी एजेंडे को रोक दे और अरब पार्टियों के साथ सहयोग करना बंद कर दे।

दुनिया खतरों से भरी है, सावधान रहना...

बेटे बैरन को मेलानिया ट्रम्प ने किया आगाह

वाशिंगटन, आरएनएन। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने बेटे बैरन को डेटिंग को लेकर एक खास सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया खतरों से भरी है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। साथ ही भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेंगी। मेलानिया (56) ने अपनी नई वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) सीरीज में यह बातें कहीं। मेलानिया ने बताया कि वह 20 साल के बैरन को अक्सर सावधान रहने की सलाह देती हैं।

इंडोनेशिया की कैंडी फैक्ट्री में आग, सात शव बरामद

50 मजदूर अब भी लापता

● जकार्ता / आरएनएन

इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के सेरांग रीजेंसी स्थित सिकांडे इलाके में एक कैंडी फैक्ट्री में शनिवार शाम लगी भीषण आग के बाद रविवार तक स्थिति बेहद गंभीर बनी रही। इंडोनेशियाई पुलिस और बचाव दलों ने अब तक 7 बॉडी बैग बरामद किए हैं, जबकि करीब 50 मजदूरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

आग लगने के एक दिन बाद भी फायरफाइटर्स कई जगहों पर हॉटस्पॉट से जूझ रहे हैं और धुएं के कारण सर्च ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। पुलिस का कहना है कि आग इतनी तेज और व्यापक थी कि बरामद किए शरीर के अंगों की पहचान सिर्फ देखकर करना लगभग असंभव है। एक बॉडी बैग में कई लोगों के शरीर के हिस्से होने की आशंका जताई है।

पुलिस आपदा पीड़ित पहचान अधिकारी वाह्यू हिदायती ने कहा कि सात बॉडी बैग बरामद किए हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस आग के पीड़ितों की पहचान देखकर नहीं की जा सकती। आग पूरी तरह बुझी नहीं है और कुछ जगहों पर अब भी गर्मी और धुआं बना हुआ है। अधिकारी पहचान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लापता मजदूरों के रिश्तेदारों से डीएनए नमूने इकट्ठा कर रहे हैं।

आज का इतिहास

- 1165: पोप एलेक्जेंडर तृतीय निर्वासन के बाद रोम वापस लौटे।
- 1744: ब्रिटिश प्रधानमंत्री जान कार्टरे ने इस्तीफा दिया।
- 1890: इटली में आम चुनाव हुये।
- 1892: लोमानी कांगो के युद्ध में बेल्जियम ने अरब को हराया।
- 1904: अमेरिका के सेंट लुईस में तीसरे ओलंपिक खेलों का समापन।
- 1926: आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा का जन्म।
- 1930: प्रसिद्ध पार्श्वगायिका गीता दत्त का जन्म।
- 1936: फोटो पत्रकारिता में एक अलग पहचान रखने वाली पत्रिका लाइफ का पहला अंक प्रकाशित।

बेपीकोलंबो मिशन — ग्रह के रहस्यों से उठेगा पर्दा, बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहा अंतरिक्ष यान

8 साल की यात्रा के बाद बुध की कक्षा में पहुंचे दो अंतरिक्ष यान

● लंदन

करीब 10 अरब किमी की आठ साल लंबी यात्रा पूरी करने के बाद बेपीकोलंबो अंतरिक्ष यान अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया है और अब बुध ग्रह की कक्षा में है। यह अंतरिक्ष यान बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहा है।

बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, जहां तापमान 430 डिग्री से. तक पहुंच जाता है और फिर गिरकर शून्य से 180 डिग्री से. नीचे तक चला जाता है। इसके अलावा, यह ग्रह लगातार तीव्र सौर विकिरण की चपेट में रहता है। अब तक इस ग्रह के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई है, लेकिन उम्मीद है कि यह मिशन बुध के कई बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इनमें यह पता लगाना भी शामिल है कि सूर्य के इतने करीब होने के बावजूद बुध के गड्ढों में बर्फ क्यों मौजूद है और इसकी पूरी सतह पर बिखरी रहस्यमयी गड्ढेनुमा संरचनाएं कैसे बनी हैं।

नासा के मिशन के दो अंतरिक्ष यान पहुंचे बुध ग्रह

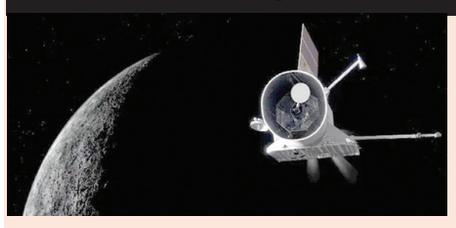

अब तक केवल दो अंतरिक्ष यान बुध तक पहुंचे हैं और दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मिशन थे। मेरिनर-10 ने 1970 के दशक में बुध के पास से तीन बार उड़ान भरी थी। इसके बाद मैसेंजर अंतरिक्ष यान 2011 में बुध पहुंचा और चार साल तक उसकी कक्षा में रहा। हालांकि, इस छोटे से ग्रह के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। बुध का आकार चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। इसकी सतह पर प्राचीन ज्वालामुखी, ऊंची चट्टानी चट्टानें और विशाल गड्ढे मौजूद हैं। बुध पर समय का गुजरना भी बेहद दिलचस्प है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा बहुत तेजी से करता है और वहां एक साल पृथ्वी के केवल 88 दिनों के बराबर होता है। लेकिन अपनी धुरी पर यह बेहद धीमी गति से घूमता है, इसलिए वहां एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित गड्ढों में बर्फ की मौजूदगी का पता लगाने के अलावा यह मिशन ग्रह की सतह पर मौजूद अजीबोगरीब धंसावों का भी अध्ययन करेगा। बुध की सतह पर ऐसे हजारों धंसाव हैं। ये उथले हैं, लेकिन इनके किनारे खड़े और तीखे हैं। अक्सर ये समूहों में दिखाई देते हैं। ग्रहों के भूवैज्ञानिक पैमाने पर ये अपेक्षाकृत युवा हैं और इनकी उम्र करीब एक लाख साल आंकी गई है।

अंतिम प्रक्रिया जोखिम भरी, 37 मिनट तक कम की यान की गति

एक रिपोर्ट में इस मिशन की प्रमुख अनुसंधानकर्ताओं में शामिल लिस्टर विवि की प्रो. एम्मा बन्स के हवाले से कहा गया कि मुझे लगता है कि आंतरिक सौरमंडल में बुध ग्रह को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है, लेकिन यही एक वजह है कि यह इतना दिलचस्प है। इसलिए पूरी यात्रा के दौरान इसकी गति नियंत्रित रखनी पड़ी। बुध की कक्षा में पहुंचने के लिए इसने बेहद घुमावदार रास्ता अपनाया। इस दौरान यान ने पृथ्वी की एक बार, शुक्र की दो बार और बुध की छह बार परिक्रमा की, ताकि इसकी गति इतनी कम हो सके कि यह ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर सके। यह यात्रा सात साल में पूरी होनी थी, लेकिन बेपीकोलंबो की प्रणोदन प्रणाली में आई समस्या के कारण पहले से ही लंबी इस यात्रा में एक साल और जुड़ गया। कक्षा में प्रवेश के लिए अंतिम प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी थी। इसमें 37 मिनट तक यान की गति को अचानक कम करने की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे बुध का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच सके। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि अंतरिक्ष यान से संपर्क स्थापित हो गया।

बुर्ज खलीफा पर न्यू ईयर 2027 का प्लान हुआ जारी

31 दिसंबर : पहली बार काउंटडाउन शो का हिस्सा होंगे सर्क डु सोले के 100 कलाकार

● नई दिल्ली

दुबई का बुर्ज खलीफा हर साल न्यू ईयर की रात होने वाली शानदार आतिशबाजी के लिए दुनियाभर में चर्चा में रहता है। लेकिन इस बार एमार ने न्यू ईयर 2027 के लिए एक खास कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें पहली बार सर्क डु सोले के कलाकार भी बुर्ज खलीफा के सामने होने वाले काउंटडाउन का हिस्सा होंगे।

यानी 31 दिसंबर 2026 को डाउनटाउन दुबई में होने वाले एमार न्यू ईयर 2027 समारोह में सर्क डु सोले की विशेष लाइव प्रस्तुति पेश की जाएगी। सर्क डु सोले की विशेष प्रस्तुति में करीब 100 कलाकार शामिल होंगे। इसके लिए एक फ्लोटिंग थिएटर तैयार किया जाएगा। यानी पानी के बीच तैयार मंच पर कलाकार अपनी पेशकश देंगे और पीछे बुर्ज खलीफा का शानदार नजारा दिखाई देगा।



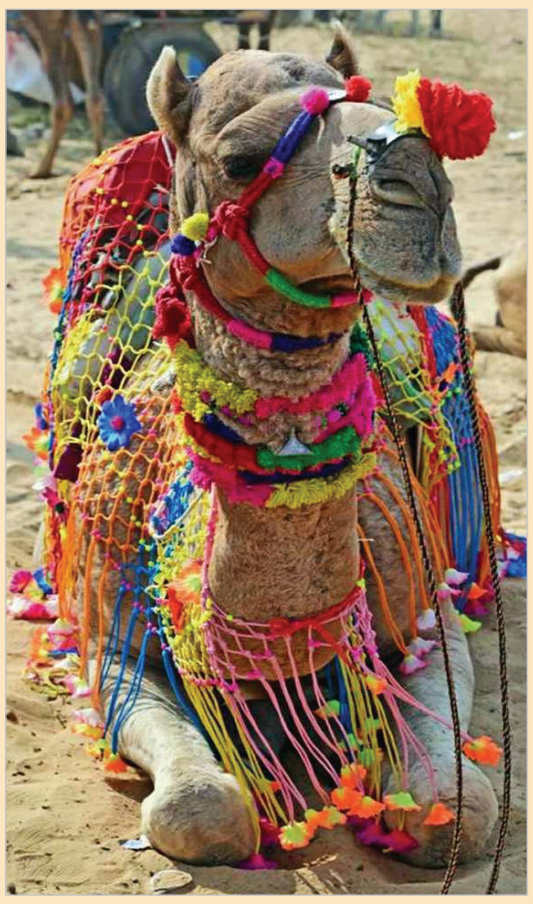

पुष्कर मेला 2026: रेगिस्तान के रंगों में जीवंत हो रही राजस्थान की संस्कृति और परंपरा

सजे-धजे ऊंटों और विदेशी सैलानियों के आकर्षण से गुलजार हुआ पुष्कर मेला

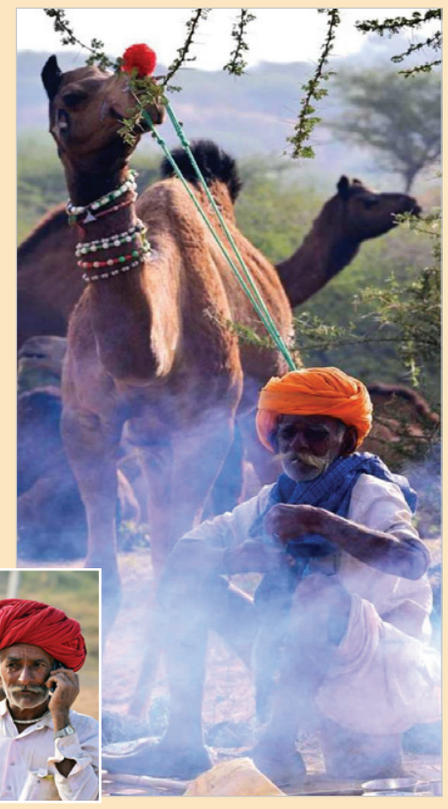

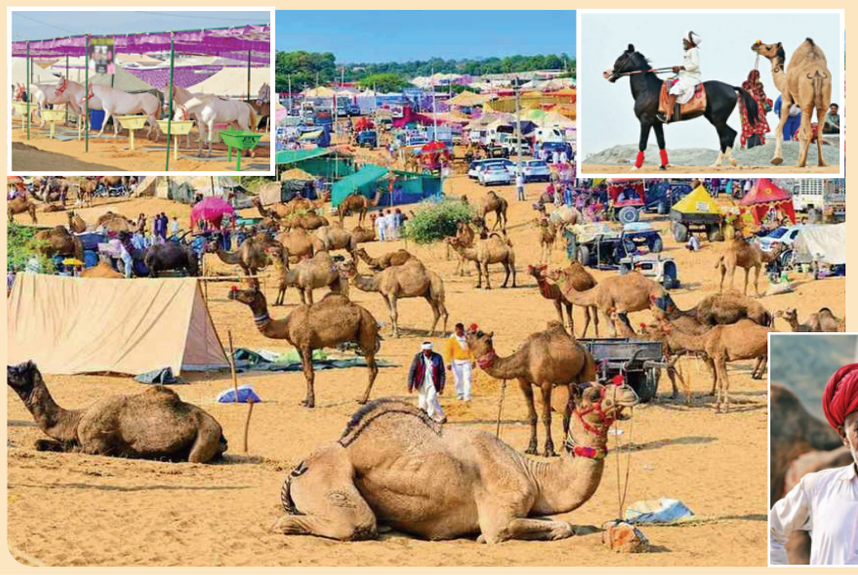

पुष्कर / जयपुर (नि.सं.)। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2026 अपने अनूठे रंगों के साथ इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 17 नवंबर से 24 नवंबर तक आयोजित हो रहे इस मेले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु और पशुपालक पहुंच रहे हैं। पुष्कर की रेतीली धरती पर सजे-धजे ऊंट, घोड़े, रंग-बिरंगी राजस्थानी पोशाकें और संगीत की गूंज यहां आने वाले लोगों को राजस्थान की असली संस्कृति से रूबरू करा रही है। पुष्कर मेला पशुओं की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की लोक कला, परंपरा, खानपान व्यापार और धार्मिक विरासत का अनूठा संगम है। मेले में राजस्थान के अलग-अलग जिलों से पशुपालक अपने ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं के साथ पहुंच रहे हैं। ऊंटों को आकर्षक आभूषणों, रंगीन कपड़ों और पारंपरिक डिजाइनों से सजाया गया है, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। पुष्कर अपने खास खानपान के लिए भी मशहूर है। यहां रबड़ी मालपुआ, खस्ता कचौड़ी..दाल-बाटी चूरमा और ऊंटनी के दूध की चाय खासतौर पर लोगो के स्वाद का केन्द्र बनी हुई हैं।

न्यूज इन बॉक्स



कानोड़िया कॉलेज की छात्राओं ने जुटाया 187 किलो प्लास्टिक कचरा

जयपुर(नि.सं.)। कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) ईकाइयों द्वारा 21 नवंबर 2026 को प्लास्टिक कचरा संग्रहण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान के तहत 187 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर बिसलेरी इंडिया लिमिटेड को पुनर्नवीनीवरण एवं पुनचक्रण के लिए दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज को यह संदेश देना था कि ÷यूज्ड प्लास्टिक कचरा नहीं है, यह पुनः उपयोग योग्य है।÷ इस पहल से यह स्पष्ट किया गया कि प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से पुनर्नवीनीकरण किया जाए तो यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के बजाय उपयोगी बन सकता है। छात्राओं और स्टाफ को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने घरों से उपयोग की हुई प्लास्टिक की बोतलें और अन्य प्लास्टिक सामग्री इस अभियान में जमा करें। स्वयंसेविकाओं ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के महत्व को समझाया। यूज्ड प्लास्टिक को कचरे में न फेंके, उसे पुनः उपयोग में लाएं जैसे नारे लगाए गए। एकत्रित प्लास्टिक सामग्री को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।



जोधपुर के महिला बाग झालरा पर डिजिटल कला का अनूठा संगम

फ्रांसीसी कलाकार की 'लेट्स ड्रॉ' परियोजना ने रंगों से सजाई विरासत

जोधपुर(वि.सं.)। जोधपुर की ऐतिहासिक धरोहर महिला बाग का झालरा कला, तकनीक और रचनात्मक कल्पनाओं के अनूठे संगम का साक्षी बना। मौक़ा था पब्लिक आर्ट ट्रस्ट ओफ़ इंडिया, अलायंस फ्रांसेज़, जोधपुर नगर निगम, द जोधपुर लॉर एवं SCWEDIA के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का। यह अपने आप में अद्भुत पहल भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के अंतर्गत आयोजित Novembre Numérique का हिस्सा रही। फ्रांसीसी कलाकार मैक्सिम टूरूट की सहभागी डिजिटल कला परियोजना 'लेट्स ड्रॉ' के तहत झालरा की दीवारों पर विशाल डिजिटल कलाकृति का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम डॉ. थियरी माथू ने किया। इस अवसर पर विधायक अतुल भंसाली, पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संस्थापक अध्यक्ष सना रिज़वान तथा अलायंस फ्रांसेज़ जयपुर की अध्यक्ष डॉ. टूलिका गुप्ता, अलायंस फ्रांसेज़ जयपुर की निदेशक संजना सरकार सहित कला एवं संस्कृति जगत से जुड़े लोग उपस्थित रहे।



विश्व सिंधी सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

प्रशासन, शिक्षा और राजनीति में सिंधी समाज की बढ़े सहभागिता : देवनानी

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दीव में आयोजित विश्व सिंधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री देवनानी ने सिंधी समाज की गौरवशाली ऐतिहासिक परम्परा, सांस्कृतिक वैभव, उद्यमशीलता, सामाजिक एकजुटता तथा राष्ट्र के प्रति उसके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंधी समाज ने विस्थापन और विषम परिस्थितियों के बीच भी अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, उद्यमिता और अदम्य संकल्प के बल पर समाज एवं राष्ट्र के विकास में विशिष्ट स्थान अर्जित किया है।



सिंधी समाज की प्रशासन शिक्षा और राजनीति में बढ़े सहभागिता

श्री देवनानी ने कहा कि भारत में सिंधी समाज की जनसंख्या एक करोड़ से अधिक है। यह समाज आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से सशक्त होने के साथ ही अपनी प्रतिभा, संगठन क्षमता और उद्यमशीलता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। देश के आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग और सामाजिक प्रगति में सिंधी समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। समाज की इस सामर्थ्य का व्यापक उपयोग राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक, शिक्षा, राजनीति, शासन-व्यवस्था, नीति निर्धारण तथा सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिंधी समाज की सहभागिता और अधिक सुदृढ़ होनी आवश्यक है।

नालसा के 'सुरक्षित बचपन अभियान' का द्वितीय चरण

चयनित 50 विद्यालयों के 79 प्रभारी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण



जयपुर(नि.सं.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जयपुर के तत्वावधान में चलाए जा रहे 'सुरक्षित बचपन अभियान' के द्वितीय चरण के तहत विद्यालय-स्तरीय क्षमता निर्माण एवं निरंतर संवेदीकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा चयनित सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों के लिए एडीआर सेंटर जयपुर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमती पल्लवी शर्मा (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय) ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत चयनित लगभग 50 सरकारी एवं निजी विद्यालयों से नामित कुल 79 शिक्षकों (यथासंभव एक पुरुष एवं एक महिला शिक्षक) को प्रशिक्षित किया गया है। सभी प्रशिक्षित शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में बाल सुरक्षा, पॉक्सो जागरूकता एवं विधिक साक्षरता के लिए रिसोर्स पर्सन डीएलएसए मेट्रो-II के रूप में कार्य कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता तथा संवेदनशील मामलों की समयबद्ध मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए सक्षम बनाना है।



शादी का टेंट हटाते समय पोल गिरा, बच्चे की मौत

मैरिज गार्डन में खेल रहा था मासूम, मां के साथ आया था ननिहाल

नागौर(वि.सं.)। नागौर में मैरिज गार्डन में शादी के बाद टेंट हटाने के दौरान लोहे का भारी पोल 7 साल के बच्चे पर गिर गया। इससे बच्चे की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सेलऊ रोड स्थित महालक्ष्मी मैरिज गार्डन में शनिवार शाम 6 बजे हुई। ASI भगवत भाकल ने बताया- यशवंत (7) पुत्र अनिल गहलोत निवासी भीकाला बास, चेनार मां के साथ ननिहाल में रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने आया था। शनिवार दोपहर में शादी हुई थी। शादी संपन्न होने के बाद शनिवार देर शाम मैरिज गार्डन में टेंट का सामान हटाने का काम चल रहा था। इसी दौरान यशवंत गार्डन में खेल रहा था। तभी अचानक लोहे का एक पोल गिर गया। पोल सीधे बच्चे के सिर पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

जयपुर पुलिस की अभिनव पहल

महिला सुरक्षा की दिशा में जयपुर पुलिस की अभिनव पहल, चार स्थानों पर शुरू हुए पिंक बूथ



जयपुर(नि.सं.)। महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पत्रिका गेट, जवाहर सर्किल पर स्थापित महिला सुरक्षा एवं सहायता बूथ (पिंक बूथ) का उद्घाटन किया। वहीं, अशोक नगर टी-पॉइंट (महारानी कॉलेज के पास), गौरव टावर के पास तथा सिटी पार्क, मानसरोवर स्थित अन्य तीन पिंक बूथों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। डीजीपी श्री शर्मा ने इस पहल के लिए पुलिस कमिश्नर श्री सचिन मित्तल एवं जयपुर पुलिस की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि महिला सुरक्षा एवं सहायता बूथ (पिंक बूथ) की स्थापना से महिलाओं एवं बालिकाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित माहौल के साथ-साथ त्वरित सहायता भी उपलब्ध हो सकेगी। पुलिस कमिश्नर श्री सचिन मित्तल ने बताया कि प्रथम चरण में जयपुर के चार प्रमुख स्थानों पर पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दो शिफ्टों में उपस्थित रहेंगी। किसी भी महिला या बालिका को आवश्यकता होने पर तत्काल सहायता, शिकायत के संबंध में मार्गदर्शन एवं आवश्यक पुलिस सहयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

महिलाओं और बालिकाओं को सार्वजनिक स्थानों पर मिलेगी त्वरित पुलिस सहायता



चूरू में पल्स पोलियो अभियान शुरू

3.24 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य, जिले में 1,180 बूथ बनाए गए

चूरू (वि.सं.)। चूरू जिले में रविवार को उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के तहत पांच साल तक के 3 लाख 24 हजार 848 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिलेभर में 1,180 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घुमंतू समुदायों, निर्माण मजदूरों और ईंट भट्ठों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चों तक पहुंचने के लिए विशेष व्यवस्था की है।

डीबी अस्पताल में अभियान का शुभारंभ

राजकीय डीबी अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. रमाकांत वर्मा ने पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की।

इमर्सिव डेस्टिनेशन

जयपुर में खुला देश का पहला इमर्सिव डेस्टिनेशन:25 से ज्यादा अट्रेक्शन प्वाइंट

घूमती सुरंग और चमकता हुआ झरना देख सकेंगे

जयपुर। अब तक मॉल में शॉपिंग, फिल्म और गेमिंग तक सीमित रहने वाला मनोरंजन का अनुभव अब एक नए अंदाज में सामने आने वाला है। जयपुर के पैसिफिक मॉल में भारत के पहले इमर्सिव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के रूप में 'जिंगवर्स' की शुरुआत हुई है। करीब 25 हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैले इस डेस्टिनेशन में 25 से ज्यादा आकर्षण तैयार किए गए हैं। यहां लोग सिर्फ मनोरंजन को देखेंगे नहीं, बल्कि खुद उसका हिस्सा बनकर अलग-अलग दुनियाओं का अनुभव कर सकेंगे। कंपनी के सीईओ गौरांग अग्रवाल ने कहा कि जिंगवर्स में उनका उद्देश्य तकनीक, रचनात्मकता और इमर्सिव अनुभवों के माध्यम से मनोरंजन की परिभाषा को नया रूप देना है। जयपुर में इसकी शुरुआत को लेकर कंपनी उत्साहित है। उम्मीद है कि शहर के परिवार और दोस्त यहां आकर मनोरंजन के नए आयामों का अनुभव करेंगे।

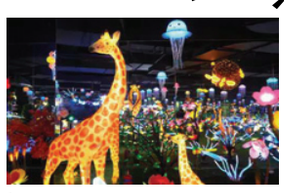

जिंगफिनिटी में आईनों का जादू, घूमती सुरंग और रंगों की अनंत दुनिया

बच्चों और परिवारों के लिए जिंगडम खास आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान दिवस पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

राजस्थानी लोक कलाओं सहित घूमर, कालबेलिया, गैर एवं चरी नृत्यों की बेजोड़ प्रस्तुतियां



नई दिल्ली/जयपुर(नि.सं.)। 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF-2026) के अंतर्गत आज प्रगति मैदान में राजस्थान दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत, लोक नृत्य एवं कलात्मक विरासत की मनमोहक झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री रोहित कुमार, मुख्य आवासीय आयुक्त के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान पवेलियन के निर्देशक श्री हर्ष शर्मा और पर्यटन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती दीपाली शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर आईटी, श्री छत्रपाल यादव और टूरिस्ट ऑफिसर श्री मनोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। लोक नृत्यों एवं पारंपरिक संगीत से सजी सांस्कृतिक संध्या। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित राजस्थान दिवस की सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत गणेश वंदना एवं चरकुला नृत्य की प्रस्तुति से हुआ, जिसे डीग के श्री मन्नू शर्मा ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात जैसलमेर के श्री हयात खां लंगा द्वारा खड़ताल वादन एवं गायन की प्रस्तुति दी।

स्वामी और प्रकाशक रमाकांत गोस्वामी एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 10 MA, आईजी नगर, जगतपुरा,जयपुर, राजस्थान - 302017 से प्रकाशित किया। संपादकः रमाकान्त गोस्वामी, उप संपादक - मोनिका शर्मा, पीआरजीआई नं. RJBIL/25/A1815 ब्रांच ऑफिसः 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल आईडीः tasneemtv.official @gmail.com, वेबसाइटः www.tasneemtv.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तदायी), किसी भी वाद-विवाद से निपटने के लिए न्यायालय जयपुर मान्य होगा।